



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]
No. 178]नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 2010/आषाढ़ 9, 1932
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 2010/ASADHA 9, 1932

वाणिज्य तथा उद्योग मंड़ालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2010

अंतिम जांच परिणाम

विषय : जापान, कोरिया गण, तथा यू.एस.ए के मूल की या वहां से निर्यातित स्टाइरिन बूटाडिन रबड़ (एस बी आर) 1900 श्रृंखला के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क—निर्णायक समीक्षा।

फा. सं. 15/25/2008-डीजीएडी.—क. 1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को व्यान में रखते हुए जापान, ताईवान, तुर्की, फ्रांस, यू.एस.ए, जर्मनी और कोरिया गण, के मूल की या वहां से निर्यातित स्टाइरिन बूटाडिन रबड़ (एस बी आर) के आयात पर 24 अगस्त, 1999 की अधिसूचना सं. 107/1999-सी.शु. के तहत मूल रूप से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. और यतः, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 3 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. 34/1/2000-डीजीएडी के तहत मध्यावधि समीक्षा में 3155-2002 की सी.शु. अधिसूचना सं. 56/2002 के तहत जापान, कोरिया, यू.एस.ए, तुर्की और ताईवान के मूल की या वहां से निर्यातित स्टाइरिन बूटाडिन रबड़ (एस बी आर) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की थी।

3. और यतः, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 27 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. 15/5/2003-डीजीएडी के तहत निर्णायक समीक्षा में जापान, कोरिया गण, तथा यू.एस.ए (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल की या वहां से निर्यातित स्टाइरिन बूटाडिन रबड़ (एस बी आर) 900 श्रृंखला (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की थी। तदनुसार पाटनरोधी शुल्क अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार 28 सितम्बर, 2004 की सी.शु. अधिसूचना सं. 100/2004 के तहत लागू किया गया था।

4. और यतः, इंडियन मैटल एंड फैरो अलायज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, रिट याचिका (सिविल) सं. 2006 की 16893 के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को व्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार प्राधिकारी ने लागू शुल्क को सतत रूप से लगाए रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने के लिए कि क्या इस प्रकार के शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए 31 मार्च, 2009 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

31 मार्च, 2009 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।

5. और यतः 28 सितंबर, 2004 की अधिसूचना सं. 100/2004 के तहत अधिसूचित पाटनरोधी शुल्क अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार 16 अक्टूबर, 2009 की सी.शु. अधिसूचना सं. 120/2009 के तहत 27 जून, 2010 तक लागू किया गया था ।

ख. प्रक्रिया

6. इस कार्यवाही में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- i. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार भारत स्थित जापान, कोरिया गण, तथा यू एस ए के दूतावासों को जांच की शुरूआत के बारे में सूचित किया गया था ।
- ii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 31 मार्च, 2009 की जांच शुरूआत अधिसूचना की प्रतियां जापान, कोरिया गण, तथा यू एस ए के भारत स्थित दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों, उसे उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार ज्ञात आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों और धरेलू उद्योग को भेजी । इस जांच के पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें और लिखित में अपने विचारों से अवगत कराएं । निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रतियां इस अनुरोध के साथ भारत स्थित जापान, कोरिया गण और यू एस ए के दूतावासों को भी भेजी गई थी कि वे संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें ।
- iii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मांगने के लिए संगत देशों के निम्नलिखित निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं :

क्र. सं.	कंपनी का नाम
1.	मै. अमेरीपोल सेनपोल कंपनी, यू एस ए
2.	मै. कोरिया कुम्हो पैट्रोकैमिकल कं. लि., सियोल, कोरिया
3.	मै. निप्पोन जिओन कंपनी लि., जापान
4.	मै. जे एस आर कार्पोरेशन, जापान

संबद्ध देशों के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है । तथापि, मै. कोरिया कुम्हो पैट्रोकैमिकल कं. लि., कोरिया ने उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में अनुरोध किए हैं ।

IV. संबद्ध वस्तु के एक प्रमुख घरेलू उत्पादक मै. एफ्को टैक्स इंड लि. ने अपने अनुरोध दायर किए हैं और वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की दलील दी है।

V. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों, प्रयोक्ताओं और एसोसिएशनों को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:

क्र. सं.	कंपनी का नाम
1.	पेरागन रबड इंड, केरल
2.	टैक्सिम इंटरनेशनल, माधावरम, मद्रास
3.	बाइकाफ रबड इंड्स, केरल
4.	मलय ट्रेड इंडेपेक्स प्रा. लि., केरल
5.	जोस्को रबरस, कालीकट
6.	पेरागन पॉलीमर प्रोडक्ट्स प्रा. लि., सलेम
7.	लीडर रबर इंड्स, कालीकट, केरल
8.	वीक्से रबड इंड, केरल
9.	सफर रबर्स, मल्लापुरम
10.	केरल फुटवियर प्रोडक्ट्स, कालीकट, केरल
11.	अरिहंत रबड एंड कैमिकल्स, कलकत्ता
12.	कैमी कलर एर्जसी, कलकत्ता
13.	वाइकिंग रबर्स प्रा.लि., केरल
14.	बॉबे पिगमेंट्स एंड एलायड प्रोडक्ट्स, केरल
15.	नियोर रबड फुट क्राफ्ट्स प्रा.लि., केरल
16.	फुटकेयर रबड इंड, केरल
17.	प्रेस्टन इंडिया प्रा.लि., बंगलौर
18.	महाराष्ट्र ट्रेडिंग कार्पॉ., मुंबई-3
19.	ऑल इंडिया रबड इंड एसो., उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में मै. पैरागन रबड इंड और मै. पैरागन पॉलीमर प्रोडक्ट्स प्रा. लि. ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं । तथापि, जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में ऋषिरूप पालीमर्स प्रा.लि., मुंबई ने अनुरोध दायर किए हैं ।

- vi. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, (डी जी सी आई एंड एस) से जांच की अवधि और पिछले तीन वर्षों के आयात के अंकहे मांगे गए थे ।
- vii. प्रधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना/अंकड़ों तथा साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा और इसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण हेतु खुला रखा ।
- viii. प्रधिकारी ने हुई क्षति का विश्लेषण करने और भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत, उसे बनाने और बेचने की लागत निकालने के लिए सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, [जी ए ए पी] के आधार पर मै. एफ्कोटैक्स इंज लि. द्वारा प्रस्तुत सूचना की संभव सीमा तक जांच की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।
- ix. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्रधिकारी ने समस्त हितबद्ध पक्षकारों को 25 फरवरी, 2010 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई मौखिक रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर भी प्रदान किया । सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त करने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था । लिखित अनुरोधों/हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त उत्तरों में दिए गए तर्कों पर इस जांच परिणामों में जहां संभव समझा गया है, विचार किया गया है ।
- x. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि अप्रैल, 2008 - मार्च, 2009 (12 माह (जांच अवधि)) की है । तथापि, क्षति विश्लेषण में 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा जांच अवधि शामिल है ।
- xi. पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार वर्तमान मामले में प्रधिकारी के समक्ष विचाराधीन आवश्यक तथ्य ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को बताए गए थे । प्रकटन दिवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर इस जांच परिणाम में विधिवत विचार किया गया है ।
- xii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के बारे में की गई थी । संतुष्ट होने के उपरांत प्रधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है । जहां संभव

हुआ है गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था ।

xiii. वर्तमान जाँच की कार्रवाई के दौरान जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने संगत सूचना जुटाने से मना किया है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डाली है वहां प्राधिकारी ने "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर ये जाँच परिणाम दर्ज किए हैं ।

xiv. *** यह चिन्ह इस अधिसूचना में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है ।

ग. प्रकटन विवरण पर टिप्पणियाँ

7(क) मै. पैरागन पॉलीमर प्रोडक्ट्स प्रा. लि. और मै. पैरागन रबड इंड. की ओर से अनुरोध

संक्षेप में निम्नलिखित टिप्पणियाँ दी गई हैं :

- उनके द्वारा पूर्व में किए अनुरोधों को इन टिप्पणियों का भाग माना जाए ।
- आधार : इस बात का उल्लेख करने के लिए विस्तृत अनुरोध किए गए थे कि आवेदन के साथ कोई अनिवार्य प्रमाणन संलग्न नहीं किए गए हैं और इस कमी का जाँच पर प्रभाव पड़ा है । माननीय प्राधिकारी ने इस अनुरोध की अनदेखी की है कि यह उल्लेख करते हुए कोई अनिवार्य प्रमाणन प्रस्तुत नहीं किया गया है कि ख्वतः कोई आयात नहीं किया गया और विचाराधीन के नियांतकों या आयातकों के साथ कोई संबंध नहीं है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदन यथापरिभाषित घरेलू उद्योग के लिए और उसकी ओर से दायर किया गया है । इसके अलावा सूचना के बारे में प्रमाणन सही और सत्य है जिसे भी दायर नहीं किया गया है ।
- नियांतकों या आयातकों के साथ आवेदक के संबंध : इस शीर्ष के अंतर्गत किए गए अनुरोधों की पूर्णतः अनदेखी की गई है । इस बात को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह जाँच करने के लिए अनिवार्य परीक्षण किया है कि क्या उन्होंने घरेलू उद्योग के लिए और उसकी ओर से दायर किए गए प्रश्नावली के उत्तर को स्वीकार किया है । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आवेदक उद्योग द्वारा की गई घोषणा और प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों के अभाव में नियम 2(ख) के परवर्ती भाग के अनुसार कोई जाँच नहीं की है । उस सीमा तक कोई जाँच नहीं की गई है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आवेदन को यथापरिभाषित "घरेलू उद्योग" के लिए और उसकी ओर से दायर किया गया माना जा सके ।
- गोपनीयता : गोपनीयता के मुद्दे को पूर्ववर्ती अनुरोधों में भी माननीय प्राधिकारी की जानकारी में लाया गया था । हमें प्रदत्त दस्तावेज भी सूचीबद्ध रूप में थे और उनसे

पाटनरोधी नियमों में की गई अपेक्षा के अनुसार पूर्ण और उचित सूचना का पता नहीं चलता था । अतः दस्तावेजों के उचित अगोपनीय रूपांतरण के अभाव में हम उन पर कोई सार्थक टिप्पणी नहीं दे सके ।

- सामान्य मूल्य एवं क्षति रहित कीमत की गणना : सादर निवेदन है कि जहाँ तक सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन और क्षति रहित कीमत की गणना की कार्यपद्धति को प्रदर्शित करने का संबंध है । प्रकटन विवरण अपर्याप्त है । इसके अलावा हमें प्रकटन विवरण का अनुबंध-4 उपलब्ध नहीं कराया गया है ।
- अपूर्ण सार्वजनिक फाइल : अनुरोध है कि सार्वजनिक फाइल में आदान-प्रदान किए गए पत्रों के अगोपनीय रूपांतरण, निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर प्रदत्त प्रत्येक दस्तावेज के अगोपनीय रूपांतरण तथा घरेलू उद्योग के लिए सत्यापन रिपोर्ट निहित नहीं हैं । डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त आंकड़े भी सार्वजनिक फाइल में नहीं रखे गए हैं ।
- विचाराधीन उत्पाद : मै. एफोटेक्स ने संबंधित वस्तु का उल्लेख हाई स्टायरिन रेजिन (एचएसआर) के रूप में किया है । हमारा निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जाँच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा को किसी भी रूप में न बदलें । हमारा यह भी निवेदन है कि केएचएस 68 को शामिल करने के लिए दायरे को बढ़ाया नहीं जा सकता जिसे किसी ऐसी स्थिति में पूर्व में विशेष रूप से अलग रखा गया है जिसमें ऐसे अपवर्जन को त्रैषिरूप पॉलिमर्स के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से आमेलित किया गया है । निर्दिष्ट प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के बारे में अपने खुद के आदेश को बहाल नहीं रख सके जिसके तहत उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार आमेलन और परिवर्तन किया गया है ।
- संभावना का विश्लेषण दोषपूर्ण है : हम यह दोहराने के लिए विवश हैं कि किसी निर्णायक समीक्षा जाँच में पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आकलन करना अपेक्षित होता है । पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में प्रकटन विवरण में पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू का विश्लेषण नहीं किया गया है । जाहिर तौर पर जाँच की वर्तमान अवधि में कोई क्षति नहीं हुई है । यह भी उल्लेखनीय है कि पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की जाँच करते समय किसी निर्णायक समीक्षा जाँच में निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण हैं :

क) संबद्ध देशों के निर्यातकों की निपटान योग्य तथा अप्रयुक्त क्षमताओं की उपलब्धता ।

ख) संबद्ध देशों के निर्यातक कम कीमतों पर अन्य देशों को संबद्ध वस्तु की आपूर्ति कर रहे हैं जिससे पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना का पता चलता है ।

ग) भारतीय बाजार में संबद्ध देशों की वस्तु की उच्चतर खपत ।

घ) निर्यातक अपने बिक्री करने के लिए नया बाजार नहीं तलाश सके और भारत में उनकी वस्तु का पाटन किए जाने की संभावना है ।

वर्तमान मामले में मै. एप्कोटेक्स ने “ क्षति संबंधी निष्कर्ष ” शीर्ष के अंतर्गत प्रश्नावली के अपने उत्तर में निम्नानुसार उल्लेख किया है :

“ घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि.....

ख. वर्तमान अवधि में आयातों की मात्रा कम थी । परिणामतः घरेलू उद्योग को सतत क्षति नहीं हुई है ।

ग. वैश्विक कीमतों में भारी गिरावट आने के कारण घरेलू उद्योग सितम्बर, 2008 के बाद अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य हुआ । कीमत में अत्यधिक गिरावट मार्च, 09 तक जारी रही ।

घ. उत्पाद की माँग में भारी गिरावट आने से घरेलू उद्योग को बिक्री मात्रा में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा और परिणामतः उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में कमी आई ।

ड. शुल्क समाप्ति की स्थिति में ” (जोर दिया गया)

मै. एप्कोटेक्स के उत्तर से उपर्युक्त उद्धरण से यह पता चलता है कि प्रश्नावली के उत्तर में किसी क्षति का दावा नहीं किया गया है । कीमतों में कमी और उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में गिरावट का कारण वैश्विक कीमत में कमी और माँग में गिरावट रहा है । ऐसी स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह जाँच करना अपेक्षित है कि क्या लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त/बंद किए जाने से पाटन तथा क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

- संभावना का विश्लेषण दोषपूर्ण है और वह ऐसे बाह्य विचारों और आंकड़ों पर आधारित है जो विचाराधीन उत्पाद से संबंधित नहीं हैं। बेशी क्षमताओं से संबंधित निष्कर्ष भी विचाराधीन उत्पाद से संबंधित आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं और इस पर ये दोषपूर्ण हैं।
- कारणात्मक संबंध : कारणात्मक संबंध का विश्लेषण भी दोषपूर्ण है क्योंकि स्वीकृत तथ्यों से यह पता चलता है कि माँग में गिरावट आई है। आवेदक पर इसके प्रभाव की जाँच करने के लिए कोई प्रभाव संबंधी विश्लेषण नहीं किया गया है। माँग में कभी के बारे में ऐसी स्वीकृति के बावजूद यह दर्ज किया गया है कि खपत की पद्धति में परिवर्तन का कोई संकेत नहीं है। माँग में गिरावट केवल खपत की पद्धति में परिवर्तन के कारण आई है।

(ख) घरेलू उद्योग के अनुरोध-

i. प्रकटन विवरण के उत्तर में घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के इस प्रस्तावित निर्धारण का विरोध किया है कि के एच एस 68 को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। इस संबंध में अपने पूर्ववर्ती अनुरोधों को दोहराते हुए घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि यद्यपि, उनके अनुरोधों का खंडन निर्यातक ने नहीं किया है, तथापि निर्यातक ने प्राधिकारी को लगातार भ्रमित किया है, उपलब्ध सामग्री से स्पष्टतः यह सिद्ध होता है कि के एच एस - 68 एस बी आर इलास्टोमर रेजिन है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से परिवर्तन हेतु पूर्ववर्ती आदेश की समीक्षा करने से प्राधिकारी वंचित नहीं होता है; प्राधिकारी ने कोई भी कारण दिए बिना उनके दावों/अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है।

ii. जहां तक जाँच के अन्य पहलुओं का संबंध है, घरेलू उद्योग प्राधिकारी के प्रस्तावित निर्धारण से सहमत है और उसने यह तर्क दिया है कि मामले के तथ्यों से पाठन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की स्पष्ट तौर पर पुष्टि होती है और पाठनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाने की जरूरत है।

(ग) मै. कुम्हो पैट्रोकेमिकल्स लि., कोरिया (निर्यातक) तथा मै. ऋषिरूप पॉलीमर्स लि. (आयातक) की ओर से अनुरोध-

i. यह अनुरोध किया गया है कि मूल जाँच में प्राधिकारी ने कभी भी यह नहीं माना है कि विचाराधीन उत्पाद में अध्याय 3903.90 के अंतर्गत वर्गीकृत एस बी आर के समस्त प्रकार शामिल हैं। इसके विपरीत प्राधिकारी ने स्पष्टतः यह नोट किया है कि अध्याय-40 में शामिल सिंथेटिक रबड़ या उसकी वस्तुओं अध्याय 39 में नहीं आती हैं। दिनांक

2006 (196) ई एल टी 129 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भी ध्यान में रखते हुए इस निर्णायक जांच में विचाराधीन उत्पाद में सी. शु. टैरिफ अधिनियम, 1975 के सी. शु. शीर्ष सं. 19 के अंतर्गत वर्गीकृत स्टायरिंग बूटाडिन रबड़ (एस बी आर) 1900 श्रृंखला के समस्त ग्रेड शामिल हैं और इसमें "इलोस्टोमर रेजिन के एच एस 68" शामिल नहीं है क्योंकि यह अध्याय-40 के अंतर्गत वर्गीकृत "सिंथेटिक रबड़" की नामावली में नहीं है।

(घ) प्राधिकारी द्वारा जाँच

- जहाँ तक "आधार" से संबंधित मुद्दे का प्रश्न है, प्राधिकारी का मत यह है कि यह मुद्दा संगत नहीं है क्योंकि एसएसआर जाँच की शुरूआत स्वतः आधार पर की गई थी।
- जहाँ तक "गोपनीयता" से जुड़े मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के बारे में संतुष्ट होने के बाद गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना को माना है। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता के दावे स्वीकार किए हैं और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया। जहाँ कहीं संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराएँ।
- जहाँ तक "विचाराधीन उत्पाद" से जुड़े मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है और इसलिए वर्तमान जाँच के क्षेत्र के बारे में प्राधिकारी द्वारा पूर्व में सूचित अंतिम जाँच परिणाम तथा माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी है। तदनुसार, प्राधिकारी प्रकटन विवरण की पुष्टि करते हैं और यह मानते हैं कि जाँच के क्षेत्र में केएचएस-68 शामिल नहीं है।
- जहाँ तक "संभावना के विश्लेषण" का संबंध है, यह स्पष्ट किया जा चुका है कि यह रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना पर आधारित है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) से पूर्णतः सुसंगत है।

21.6.99 के उक्त अंतिम जांच परिणामों को एक हितबद्ध पक्षकार ने माननीय सीगेट, नई दिल्ली में चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण ने अपने विवेकानुसार यह निर्णय लेते हुए दिनांक 2.2.2000 के आदेश के तहत प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम को उलट दिया कि पाटनरोधी शुल्क एस बी आर के समस्त ग्रेडों पर लागू है भले ही वे उपशीर्ष 4002 या 3903 के अंतर्गत आते हैं। प्राधिकरण के आदेश के अनुसरण में प्राधिकारी ने दोनों अंतर्वर्ती समीक्षाओं अर्थात् मध्यावधिक समीक्षा-I और निर्णायक समीक्षा-I में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को बढ़ाया था। तथापि, अपील करने पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 23.3.06 के अपने निर्णय में मूल जांच में प्राधिकारी के आदेश को बहाल रखा।

ii इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसरण में मूल जांच में प्राधिकारी के विचाराधीन उत्पाद से संबंधित अंतिम जांच परिणाम आज भी विधिसम्मत हैं। प्राधिकारी ने यह निर्धारण करने के बाद कि उप शीर्ष 3903.90 के अंतर्गत आने वाली मदें विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं थीं, इसलिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रयोजनार्थ वर्तमान जांच में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, प्राधिकारी ने स्पष्टतः यह नोट किया था कि "अध्याय-39 के अंतर्गत स्वीकृत मद "इलास्टोमर रेजिन के एच एस 68" थी और इस प्रकार यह "सिंथेटिक रबड़" की नियमावली में शामिल नहीं थी। इसका अनुसर्थन माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह दर्ज करते हुए किया था कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दर्ज जांच परिणाम स्पष्ट हैं और इनमें कोई लिपिकीय चूक नहीं हुई है"

iii उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अनुरोध है कि प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित को विशिष्ट रूप से रिकार्ड किया जाए :

यह पाया गया है कि मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद जापान, कोरिया गण, और यू.एस.ए के मूल के या वहां से निर्यातित सी.शु. टैरिफ अधिनियम, 1975 के सी.शु. शीर्ष सं. 3903.90 और 400.19 के अंतर्गत वर्गीकृत स्टायरिंग बूटाडिन रबड़ (एस बी आर) के समस्त ग्रेड थे। मूल जांच 2.6.99 की अधिसूचना के तहत संपत्र की गई थी और एस बी आर 1500, 1700 एवं 1900 श्रृंखला पर शुल्क की सिफारिश की गई थी। तथापि, 3 जुलाई, 2001 की मध्यावधिक समीक्षा अधिसूचना के तहत शुल्क का क्षेत्र एस बी आर 1900 श्रृंखला तक सीमित कर दिया गया था और इसे प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में बरकरार रखा गया था। उपर्युक्त और ऋषिरूप पालीमर्स प्रा. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अपर सचिव,

- उठाए गए अन्य सभी मुद्दों पर इन जाँच परिणामों के संगत खण्ड में उचित कार्यवाही की गई है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

घ. घरेलू उद्योग के अनुरोध

8. मै. एफ्को टैक्स इंड लि. ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद 1500, 1700 तथा 1900 श्रृंखला की स्टाइरिन बूटाडिन रबड़ (एस बी आर) के समस्त ग्रेड थे। मध्यावधि समीक्षा जांच द्वारा शुल्क का दायरा एस बी आर 1900 श्रृंखला तक सीमित किया गया था और उसे प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में बरकरार रखा गया था। वर्तमान द्वितीय निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही अर्थात् 1900 श्रृंखला की स्टाइरिन बूटाडिन रबड़ (एस बी आर) के समस्त ग्रेड हैं जिसका उल्लेख हाई स्टाइलिंग रेजिन मास्टर बैच अथवा इमल्सन रेजिन रबड़ मास्टर बैच के रूप में किया गया है।
- एस बी आर 1900 श्रृंखला 2 लेटेक्सों- स्टाइरिन बूटाडिन रबड़ लेटेक्स और हाई स्टायरिंग रेजिन लैटेक्स के मास्टर बैच की मिश्रण है। एस बी आर 1900 श्रृंखला सिंथेटिक रबड़ है क्योंकि वह रबड़ की तकनीकी परिभाषा पर खरी बैठती है।
- यह 4 अंकीय स्तर पर उप शीर्ष सं. 40.02 के अंतर्गत वर्गीकृत है। इसे उप शीर्ष 4002.19 (50% से अधिक के स्टायरिंग घटक वाली स्टायरिंग बूटाडिन रबड़) के अंतर्गत रबड़ के रूप में श्रेणीबद्द किया गया है। वस्तुतः जब ग्रेड के स्टायरिंग घटक में आगे वृद्धि होती है तो ग्रेडों की निकासी सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के उप शीर्ष 3903.90 के अंतर्गत की जा सकती है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।
- एस बी आर 1900 श्रृंखला के ग्रेडों का सामान्यतः उल्लेख उत्पाद में सद्व्यारिंग घटक और मूमी विस्कोसिटी के संबंध में किया जाता है। एस बी आर 1900 श्रृंखला में स्टायरिंग तथा मूमी विस्कोसिटी के घटक का % अन्य ग्रेडों की तुलना में एस बी आर 1900 श्रृंखला के एक ग्रेड से अलग होते हैं। समस्त ग्रेडों को अनुप्रयोग के चरण पर उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए अदल-बदल कर उपयोग में लाया जाता है। भारतीय उद्योग द्वारा एस बी आर 1900 श्रृंखला के ग्रेडों का उत्पादन किया जाता है जो संबद्ध देशों में निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा उत्पादित उन समस्त ग्रेडों के समतुल्य हैं।
- कारिया गण. के निर्यातकों ने यह दावा करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी को भ्रमित किया है कि उनके द्वारा उत्पादित और आपूर्त केएचएस-68 ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आता है। यद्यपि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि हाई स्टायरिंग रेजिन मास्टर बैच पाटनरोधी शुल्क के दायरे में आता है।
- के एच एस - 58 ग्रेड इस अपवाद के साथ के एच एस -68 से अत्यंत तुलनीय है कि के एस एच - 58 में स्टायरिंग घटक कम होता है और इसलिए के एस एच-68 सी. श. अधिनियम के अध्याय 40 में आता है।

(vii) विनिर्माण प्रक्रिया के फ्लों चार्ट से यह पता चलता है कि यह दो लेटेक्सों का एक मास्टर बैच है जैसा कि एस बी आर 1900 श्रृंखला के मामले में है । मै. सी एम ब्लो के अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त एक अन्य साहित्य से भी यह पता चलता है कि मास्टर बैच के रूप में उल्लिखित वस्तु एस बी आर 1900 श्रृंखला है । के एच एस - 68 मास्टर बैच के अलावा कुछ नहीं है ।

(viii) अंतर्राष्ट्रीय सिंथेटिक रबड उत्पादक संस्थान (आई आई एस आर पी) ने विभिन्न एस बी आर श्रृंखलाओं को परिभाषित किया है । आई आई एस आर पी ने एस बी आर 1900 श्रृंखला को इमल्सन रेजिन रबड मास्टर बैच के रूप में परिभाषित किया है । के एच एस - 68 भी के एच एस इमल्सन रबड मास्टर बैच है ।

(ix) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल जांच से संबंधित अपने प्रारंभिक जांच परिणामों (जनवरी, 99) में यह उल्लेख किया था कि एस बी आर 1900 श्रृंखला (हाई स्टायरिन रेजिन मास्टर बैच) विचाराधीन उत्पाद में शामिल है । के एच एस 68 और कुछ नहीं है अपितु एस बी आर 1900 श्रृंखला है और इस प्रकार यह शुल्क योग्य है ।

(x) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल जांच से संबंधित अपने अंतिम जांच परिणामों (अगस्त, 99) में यह उल्लेख किया था कि जहां तक विशिष्ट श्रेणियों का एस बी आर आयातित उत्पाद है, वहां तक उस पर पाटनरोधी शुल्क लागू होना चाहिए (भले ही उसके आयात का सी.शु. शीर्ष कुछ भी हो) । तदनुसार सी.शु. विभाग ने इस बात का निर्धारण किया है कि क्या आयातित मद विशिष्ट श्रृंखलाओं की एस बी आर है और उस पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है ।

(xi) मूल जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश को कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने सेस्टेट में चुनौती दी थी । सेस्टेट ने अपने आदेश में अन्य बातों के साथ साथ यह उल्लेख किया कि पाटनरोधी शुल्क एस बी आर पर लगू है भले ही उसका आयांत 4002.19 या 3903.90. के अंतर्गत किया गया हो । तदनुसार पाटनरोधी शुल्क दोनों सीमाशुल्क कोडों पर लागू किया गया है ।

(xii) सी.शु. विभाग ने के एच एस 68 के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू किया है । इस प्रकार की लेवी में से एक लेवी को रिलेक्सो द्वारा सेस्टेट में चुनौती दी गई थी और इस आशय की गलत बयानी की थी कि शामिल उत्पाद एस बी आर नहीं है । सेस्टेट ने यह माना था कि पाटनरोधी शुल्क की गलत वसूली की गई है । तथापि, वित्त मंत्रालय ने सेस्टेट के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है । तत्पश्चात् सी.शु. विभाग ने समस्त सीमाशुल्क के ग्रहों को देश में सूचित के एच एस 68 के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क वसूलने के निर्देश दिए हैं । रिलेक्सो द्वारा के एच एस 68 के बाद में किए गए परेषण पर पुनः पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था ।

(xiii) रिलेक्सो ने इस आदेश को सेस्टेट में पुनः चुनौती देते हुए अंततः एक अपील दायर की । तथापि इस समय तक चूंकि वित्त मंत्रालय को सेस्टेट के समक्ष गलतबयानी के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वित्त मंत्रालय ने उत्पाद के बारे में तकनीकी सूचना जिसे रिलेक्सों और कोरिया के निर्यातक ने छिपाया था, सहित पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया । सेस्टेट ने समस्त पक्षकारों के विस्तृत तर्कों के साथ-साथ प्रति जांच सहित यह माना कि रिलेक्सो का प्रतिनिधित्व गलत था और सीमाशुल्क विभाग को इस मामले की नए सिरे से जांच करनी चाहिए । तदनुसार यह मामला सीमाशुल्क विभाग के पास वापस भेज दिया गया था । सीमाशुल्क विभाग ने के एच एस 68 से संबंधित समस्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद इस बात की पुष्टि की है कि के एच एस 68 पर पाटनरोधी शुल्क लगाना अपेक्षित है ।

(xiv) एच एस 68 का उत्पादन और बिक्री करने वाली के कंपनी के के पी सी द्वारा 90 के दशक की शुरूआत से लेकर कई वर्षों तक के एच एस 68 का विज्ञापन एस बी आर के रूप में किया जा रहा था। पाटनरोधी शुल्क के अपवंचन और प्रमुख तथ्यों को छुपाने के लिए जब पाटनरोधी शुल्क का मुद्दा उत्पन्न हुआ तो विज्ञापन यह प्रदर्शित करने के लिए बदल दिय गया कि के एच एस 68 उच्च स्टायरिंग रेजिन है। और में परिवर्तन के बावजूद उत्पाद के आवश्यक गुणधर्म, कार्य एवं उपयोग तथा ग्राहक वही बने हुए हैं।

(xv) के के पी सी की विवरणिकाओं में के एच एस 68 को उच्च स्टायरिंग रबड़ के रूप में स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि कंपनी इस उत्पाद को "रबड़" के रूप में प्रदर्शित करती है न कि "रेजिन" या "प्लास्टिक" के रूप में क्योंकि कंपनी अब इस दावे का प्रयास कर रही है।

(xvi) आई आई टी, खड़गपुर-पोलीमर विभाग ने यह राय व्यक्त की है कि के एच एस 68 एस बी आर 1900 श्रृंखला के अंतर्गत आना चाहिए। इसी प्रकार की राय अन्य स्वतंत्र संगठनों और कई विशेषज्ञों ने व्यक्त की है।

(xvii) के एच एस 68 पर पाटनरोधी शुल्क लगाने को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। समूचे प्रकरण की सुनवाई करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने दिसंबर, 01 में यह निर्णय दिया कि के एच एस 68 पाटनरोधी शुल्क के योग्य है।

(xviii) के एच एस 68 का अंतिम उपयोग घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और विश्व भर के अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित एस बी आर 1900 के समरूप है अर्थात इसका फुटवियर में अनुप्रयोग होता है। उपभोक्ताओं के ऐसे अनेक पत्र रिकार्ड में उपलब्ध हैं जिनमें यह बताया गया है कि के एच एस 68 कर अदल-बदल कर उपयोग घरेलू उत्पादकों की एस बी आर 1900 श्रृंखला और/अथवा विश्व भर के अन्य आपूर्त एस बी आर 1900 श्रृंखला की रबड़ के स्थान पर किया जा रहा है।

(xix) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई मध्यावधि समीक्षा जांच में यह बात दोहराई गई है कि विचाराधीन उत्पाद एस बी आर 1900 श्रृंखला हाई स्टायरिंग रेजिन मास्टर बैच है। के एच एस 58, के एच एस 65 और के एच एव 68 उच्च स्टायरिंग रबड़ शीर्ष में शामिल हैं। इन ग्रेडों का अनुप्रयोग सामान्य है।

(xx) के के पी सी की पुस्तिकाओं में के एच एस 68 को एच एस आर/हाई स्टायरिंग रेजिन मास्टर बैच के रूप में प्रदर्शित किया है है; विनिर्माण प्रक्रिया का उल्लेख एस बी आर लेटेक्स तथा उच्च स्टायरिंग रेजिन लेटेक्स के रूप में किया गया है जो एस बी आर 1900 श्रृंखला की सही परिभाषा पर खरी उत्तरती है।

(xxi) घरेलू उद्योग ने मै. के के पी सी की वैबसाइट का हवाला दिया है जिसमें यह पाया गया था कि कंपनी ने विभिन्न उत्पादों को सिंथेटिक रबड़ "सिंथेटिक रेजिन" शीर्ष में प्रदर्शित किया है। यह पाया गया है कि हाई स्टायरिंग रबड़ को सिंथेटिक रबड़ शीर्ष में शामिल किया गया है। इसके अलावा, हाई स्टायरिंग रबड़ (एस एस आर) से संबंधित वैब पेज/विवरण में उत्पाद की व्याख्या हाई स्टायरिंग रेजिन मास्टर बैच के रूप में की गई है।

(xxii) चूंकि एस बी आर 1900 श्रृंखला में हाई स्टायरिंग रेजिन मास्टर बैच शामिल हैं, इसलिए इसमें यह माना जाता है कि हाई स्टायरिंग रेजिन मास्टर बैचों के समस्त ग्रेड एस बी आर 1900 श्रृंखला में शामिल हैं। तदनुसार के एच एस 68 विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में पर्याप्तता: आता है।

(xxiii) निर्यातकों ने यह तर्क दिया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी इस मुद्दे की समीक्षा नहीं कर सकते कि क्या के एच एस 68 एस बी आर 1900 श्रृंखला है अथवा नहीं। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने गुण-दोष के बारे में

कोई निर्णय नहीं लिया है। उसने केवल निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय की व्याख्या करने का प्रयास किया है। इस मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस मुद्दे की समीक्षा नहीं कर सकते।

(xxiv) पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जांच में केवल एच एस 68 के आयात हुए थे और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने शुल्क की अवधि बढ़ाने की सिफारिश करते हुए पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच की थी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विगत में यह माना है कि के एच एस 68 एस बी आर 1900 श्रृंखला नहीं है।

(xxv) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एस बी आर 1900 श्रृंखला के तकनीकी विनिर्देशन संबद्ध देशों से निर्यातित विनिर्देशनों के समान है। इसके अलावा यह संबद्ध देशों से आयातित एस बी आर 1900 श्रृंखला के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। आयातित और घरेलू रूप से उत्पादित सामग्री का उपयोग दोनों उत्पादों के बीच प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा के साथ एक-दूसरे के साथ किया जा रहा है। दोनों उत्पाद समस्त आवश्यक, भौतिक और तकनीकी विशेषताओं के संबंध में समान हैं।

(xxvi) समान वस्तु के मुद्दे का निर्धारण निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती जांचों में और सीधे किया गया है जिसमें घरेलू उद्योग तथा संबद्ध देशों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को समान वस्तु माना गया है।

घ.2. आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

9. आयातकों (मै. पैरागन रबड़ इंडस्ट्रीज तथा मै. पैरागन पॉलीमन प्रा.लि.) ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- (i) एच एस 68 को शामिल करने के लिए मौखिक सुनवाई में किए गए अनुरोध कभी भी आवेदन का भाग नहीं रहे हैं और इन्हें पहली बार उठाया गया है।
- (ii) उत्पाद के क्षेत्र का विस्तार समीक्षा के इस चरण पर नहीं किया जा सकता।

9.1 मै. कोरिया कुमको पैट्रोकैमिक कं. लि., सियोल, कोरिया (के के पी सी) ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- (i) एस बी आर के समस्त प्रकार जांच में शामिल नहीं किए गए थे और यह सी. शु. शीर्ष 3903.90 के अंतर्गत एस बी आर को वर्गीकृत करने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ है।
- (ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने प्रारंभिक जांच परिणामों में यह माना है कि शीर्ष 3903.90 के अंतर्गत एस बी आर विचाराधीन उत्पाद नहीं है। अपने अंतिम जांच परिणाम में यह भी माना गया था कि अध्याय-39 के अंतर्गत आने वाला के एच एस 68 जांच के दायरे से बाहर है।
- (iii) सी. शु. शीर्ष 3903.90 के अंतर्गत एस बी आर को शामिल करना उच्चतम न्यायालय की अवमानना होगी।

(iv) सी गैट के आदेश के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे में एम टी आर तथा एस एस आर में विस्तार किया है।

(v) किसी निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में संशोधन नहीं किया जा सकता। वस्तुतः वर्तमान समीक्षा दूसरी निर्णायक समीक्षा है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. एप्कोटैक्स इंड. लि. ने यह तर्क दिया है कि के एच एस 68 एक एस बी आर है और वह विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आता है और यह कि निर्यातकों तथा आयातकों ने यह मानने के प्राधिकारी को भ्रमित किया है कि "इलास्टोमर रेजिन के एच एस 68" "सिथेटिक रबड़" की नामावली में शामिल नहीं है और यह कि एच एस 68 का अत्यधिक आयात जांच अवधि के दौरान हुआ है।

11. तथापि यह नोट किया जाता है कि 2 जून, 1999 के अंतिम जांच परिणाम के पैरा 7 में प्राधिकारी ने निम्नानुसार दर्ज किया है:

"7... प्राधिकारी ने यह पाया है कि अध्याय 39 के अंतर्गत स्वीकृत मद "इलास्टोमर रेजिन पेस्ट" है और इस प्रकार यह "सिथेटिक रबड़" की नामावली में शामिल नहीं है। इस बात के मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने उप शीर्ष 3903.90 के अंतर्गत आने वाली मद को शामिल करने में औचित्य नहीं पाया है। तथापि, प्राधिकारी याचिकाकर्ता के तर्क पर उस सीमा तक सहमत हैं कि विचाराधीन उत्पाद उल्लेखानुसार विनिर्दिष्ट शृंखलाओं की सिथेटिक बूटाडिन रबड़ है भले ही उसका सीमाशुल्क शीर्ष कुछ भी हो। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रयोजनार्थ उप शीर्ष 3903.90 के अंतर्गत आने वाली सभी मदों को शामिल करना औचित्यपूर्ण नहीं है, तथापि, वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क उल्लेखानुसार विनिर्दिष्ट शृंखलाओं की स्टायरिंग बूटाडिन रबड़ पर संदेय है। यद्यपि, इसकी निकासी की मांग सी. शु. टैरिफ अधिनियम के किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत की जाती है। सी. शु. प्राधिकारी के पास इस बात की स्वतंत्रता है और उनसे यह आशा की जाती है कि वे स्वीकृति हेतु प्रस्तुत वस्तु का सही वर्गीकरण न होने की स्थिति में उक्त वस्तु को सही ढंग से वर्गीकृत करें।

12. यह पाया गया है कि मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद जापान, कोरिया गण. और यू.एस.ए के मूल के या वहां से निर्यातित सी.शु. टैरिफ अधिनियम, 1975 के सी. शु. शीर्ष सं. 3903.90 और 400.19 के अंतर्गत वर्गीकृत स्टायरिंग बूटाडिन रबड़ (एस बी आर) के समस्त ग्रेड थे। मूल जांच 2.6.99 की अधिसूचना के तहत संपन्न की गई थी और एस बी आर 1500, 1700 एवं 1900 शृंखला पर शुल्क की सिफारिश की गई थी। तथापि, 3 जुलाई, 2001 की मध्यावधिक समीक्षा अधिसूचना के तहत शुल्क का क्षेत्र एस बी आर 1900 शृंखला तक सीमित कर दिया गया था और इसे प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में बरकरार रखा गया था। इस प्रकार इस निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद वही रहता है अर्थात स्टायरिंग बूटाडिन रबड़ (एस बी आर) 1900 शृंखला के समस्त ग्रेड और इसमें "इलोस्टोमर रेजिन पेस्ट" शामिल नहीं है।

13. तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

ड.1. घरेलू उद्योग का क्षेत्र

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

14. मै. एप्कोटैक्स इंडस्ट्रीज लि. ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

मूल जांच में याचिका मै. सिंटेक्स इंड कैमिकल्स लि. द्वारा दायर की गई थी । बाद में कंपनी अपना उत्पादन बंद करने के लिए बाध्य हुई थी । समीक्षा के समय मै. अपार इंडस्ट्रीज लि. तथा एफकोटैक्स इंड लि. घरेलू उद्योग थे । वर्तमान अवधि में भारत में एस की बार के केवल दो उत्पादक हैं । एफकोटैक्स भारत में संबद्ध वस्तु का एक प्रमुख उत्पादक है ।

ड.2. आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

15. आयातकों (मै. पैरागन रबड इंडस्ट्रीज तथा मै. पैरागन पोलीमर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.) ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

(i) वर्तमान उत्तर घरेलू उद्योग की ओर से प्राधिकार रहित हैं । यह धोषणा कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है अथवा वह निर्यातक या आयातक से संबद्ध नहीं है, प्रमाणन रहित है । प्राधिकारी ने इस संबंध में कोई जांच नहीं की है ।

(ii) व्यापार सूचना स. 3/2007¹ अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच को उस स्थिति में बंद करने के लिए स्वतंत्र होता है यदि विधिवत पुष्टिकृत आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा दायर न किया गया हो ।

(iii) एफकोटैक्स ने उचित कारण दिए बिना क्षति एवं कारणात्मक संबंध से संबंधित समस्त सूचना को अनावश्यक रूप से गोपनीय माना है । अगोपनीय सूचना के बारे में कोई उचित सूचीकरण नहीं किया गया है अतः ऐसी सूचना अस्वीकार्य है ।

16. इस संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है ।

ड. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

17. इस समीक्षा जांच की शुरुआत के समय पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नानुसार उल्लेख है :-

"(ख)"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाठित वस्तु के नियांतकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा ।"

18. तथापि, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

"(ख)"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाठित वस्तु के नियांतकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा ।"

19. वर्तमान समीक्षा जांच में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै. एफ्कोटैक्स इंड. लि. भारत में संबद्ध वस्तु का एक प्रमुख उत्पादक है। अतः मै. एफ्कोटैक्स इंड लि. पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" है।

च.1. पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

20. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- संबद्ध देशों के किसी भी नियांतक और उत्पादक ने नियांतक प्रश्नावली का उत्तर दायर कर निर्दिष्ट प्राधिकारी का उत्तर नहीं दिया है। मै. कोरिया कुम्हो पैट्रो कैमिकल कं. लि., सियोल, कोरिया (के के पी सी) ने भी प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर नहीं किया है। यद्यपि, कंपनी ने जांच अवधि में संबद्ध वस्तु का नियांत किया है। ऐसी स्थिति होने के कारण समस्त संबद्ध देशों के नियांतकों/उत्पादकों को असहयोगी मानाजाना चाहिए।
- घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य का विस्तृत अनुमान उपलब्ध कराया है जिसे वर्तमान समीक्षा में पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु अपनाया जा सकता है।
- डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रदर्शित आयातों पर विचार नहीं किया जा सकता। एस बी आर 1900 श्रृंखला सीमाशुल्क उप शीर्ष सं. 4002.1902 और 3903.9000. के अंतर्गत वर्गीकृत है। आयातक इसकी निकासी अन्य उपशीर्षों के अंतर्गत करवा रहे हैं। वाणिज्यिक आसूधना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के आंकड़ों में आयातों की मात्रा और मूल्य के बारे में सही और पूर्ण स्थिति का पता नहीं चलता है। उन्होंने यह सिद्ध करते हुए साक्ष्य प्रदान किया है कि आयातक अन्य उपशीर्षों के अंतर्गत भी एस बी आर 1900 श्रृंखला की निकासी करवा रहे हैं। इसके अलावा, सी.शु. उप शीर्ष 3903.9000 में एस बी आर श्रृंखला के अलावा अन्य उत्पादों के आयात

भी शामिल हैं । अतः अनुरोध है कि डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रदर्शित आयातों पर विचार न किया जाए ।

- उन्होंने सीमाशुल्क उपलब्ध कराई गई सूचना और गौण स्रोतों से संकलित सूचना के अनुसार आयात के आंकड़ों को संकलित किया है । एस बी आर 1900 श्रृंखला के ऐसे आयातों को संकलन सी.शु. की दैनिक सूचियों में उपलब्ध सूचना के आधार पर पालीमर्स प्लास्टिक्स एंड रबड जर्नल (पी पी आर) द्वारा किया जा रहा है । अनुरोध है कि पी पी आर द्वारा प्रकाशित सूचना के अनुसार संकलित आयातों पर भारत में संबद्ध वस्तु के न्यूनतम आयातों के रूप में विचार किया जा सकता है । अतः घरेलू उद्योग ने पी पी आर में प्रदर्शित आयातों के अनुसार उपर्युक्त कारणों की वजह से निर्यात कीमत निर्धारण की है ।
- यह नोट किया जा सकता है कि यद्यपि आयातों की निकासी सी.शु. टैरिफ के अध्याय 40 के अंतर्गत की गई है तथापि, इन देशों के विनिर्माता विभिन्न ग्रेडों का उत्पादन करने की स्थिति में हैं जिनमें से कुछ सी.शु. कोल्ड के अध्याय 39 के अंतर्गत आते हैं । अतः यह आवश्यक है कि पाटनरोधी शुल्क समस्त संगत सीमाशुल्क कोडों पर लागू किया जाए ।
- सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए यह देखा जाएगा कि संबद्ध देशों के निर्यातकों ने भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर निर्यात जारी रखा है । किसी भी विदेशी निर्यातक या उत्पादक ने निर्धारित प्रपत्र और ढंग से सूचना प्रदान नहीं की है । इसके अलावा, किसी भी विदेशी निर्यातक या उत्पादक ने यह भी सिद्ध नहीं किया है कि "कोई पाटन" नहीं हुआ है अथवा "पाटन की कोई संभावना नहीं है" । निर्यातक यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन होने की संभावना नहीं है ।
- किसी निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी के लिए पाटन और क्षति के जारी रहने या उवका पुरावृत्ति होने की संभावना की जांच अपेखित होती है ताकि पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को जारी रखने अथवा उसकी राशि को घटाने-बढ़ाने अथवा उसको समाप्त करने के बारे में कोई निर्णय लिया जा सके । अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अनुरोध किया गया है :

 - (i) कि घरेलू उद्योग को कुछ समय से पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है जैसी कि मूल निर्धारण और परवर्ती समीद्वक्षा निर्धारणों में पुष्टि की गई है । इस बात की प्रबल संभावना है कि शुल्क समाप्त किए जाने से भारतीय बाजार में सामग्री की भरमार हो जाएगी । कि घरेलू उद्योग को आयातों की कम मात्रा के कारण वर्तमान अवधि में कोई खास क्षति नहीं हुई है । तथापि, पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर संवर्धित मात्रा आने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी ।

(ii) कि संबद्ध सामग्री का निर्यात और उसकी बिक्री घरेलू बाजार में करने के बाद भी इन देशों के उत्पादकों के पास अतिरिक्त अप्रयुक्त क्षमताएं बची हुई हैं। ये बेशी क्षमताएं स्पष्ट तौर पर निर्यात बाजारों को देखते हुए सूजित की गई हैं। अतः वर्तमान शुल्क समाप्त किए जाने से भारतीय बाजार में पर्याप्त निर्यात होंगे।

(iii) कि जांच अवधि में सूचित आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही थी। अतः पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को इस उत्पाद की मांग में गिरावट का सामना करने की संभावना है। इसका घरेलू उद्योग पर अत्यधिक हासकारी/न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा।

(iv) यह सिद्ध करने का दायित्व निर्यातक का है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है।

च.2. निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. न तो किसी निर्यातक और न ही उत्पादक ने निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने पाटन मार्जिन के निर्धारण निर्धारण हेतु सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत के संबंध में कोई टिप्पणी, अनुरोध प्रस्तुत किया है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

22. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु का जापान से 29 मी.ट. का ही आयात हुआ है और कोरिया मण. तथा यू.एस.ए जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का कोई आयात नहीं हुआ है। आगे यह नोट किया जाता है कि लगभग 9000 मी.ट. की कुल मांग में से संबद्ध देशों से हुए आयात केवल 29 मी.ट. के रहे हैं अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि संबद्ध वस्तु के इतनी मात्रा में हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोई खास प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तथापि, इस बात की संभावना है कि ये आयात लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण न हुए हों।

23. अतः नियमों में की गई अपेक्षा के अनुसार प्राधिकारी ने लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृति होने की संभावना की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि अन्य बातों के साथ-साथ पाटन की पुनरावृति होने और परिणामी क्षति होने की संभावना से संबंधित सूचना मांगते हुए एक विशिष्ट प्रश्नावली संबद्ध देशों के सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को भेजी गई थी। तथापि, किसी निर्यातक/उत्पादक ने इसका उत्तर नहीं दिया है और इस प्रकार इस जांच में सहयोग नहीं किया है। अतः प्राधिकारी के पास पाटन की पुनरावृति होने की संभावना की जांच करने के लिए रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अतः प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर पाटन की पुनरावृति होने और परिणामी क्षति होने की संभावना के मुद्दे की जांच की है।

24. प्राधिकारी ने ऐसे संगत आंकड़ों का पता लगाने का प्रयास किया जिनसे उस कीमत का पता लगाया जा सके जिस कीमत पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का निर्यात तीसरे देश के

बाजारों को किया गया है। इस प्रयोजनार्थ कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसो. (के आई टी ए), अन्कामट्रेड तथा वर्ल्ड ट्रेड एटलस द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि संबद्ध वस्तु के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इनमें एस बी आर के समस्त प्रकार शामिल हैं। यह पाया गया था कि इस उत्पाद के लिए सी. शु. वर्गीकरण अनन्य नहीं है और इस वर्गीकरण में एस बी आर के अन्य प्रकार भी शामिल हैं।

25. घरेलू उत्पादक ने एक रिपोर्ट अर्थात् आई आई एस आर पी की वर्ल्ड रबड स्टेटिक्स, 2008 प्रस्तुत की है (इस उत्पाद से संबंधित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका जिसमें विभिन्न वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के पास उपलब्ध क्षमताओं और विश्वव्यापी खपत की पद्धतियों के ब्यौरे निहित हैं)। इस रिपोर्ट के अवलोकन से यह नोट किया जाता है कि वैश्विक रूप से उत्पादकों की रिपोर्ट में समग्र एस बी आर की क्षमताएं निहित हैं भले ही उनका प्रकार कुछ भी हो। तथापि, इस पत्रिका के अवलोकन से यह पता चलता है कि संबद्ध देशों में एस बी आर के विनिर्माण हेतु बेशी क्षमताएं हैं जिनमें संबद्ध वस्तु भी शामिल है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि कुछेक वैश्विक उत्पादक वस्तुतः एस बी आर के अलग-अलग स्वरूपों का उत्पादन करने के लिए उत्पादन क्षमताओं का अदल-बदल कर उपयोग कर रहे हैं। संबद्ध वस्तु के कुछ उत्पादकों की वैबसाइटें भी देखी गई थीं परंतु क्षमताओं और उसके अन्य ब्यौरों के बारे में सूचना नहीं मिली थी। यद्यपि इन वैबसाइटों में संबद्ध वस्तु के उत्पादन, क्षमता, मांग आदि से संबंधित सूचना का पता नहीं चला, परंतु इनमें उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पादों के संबंध में सूचना मात्र का पता चला।

26. तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से 29 मी.ट. संबद्ध वस्तु का आयात किय गया है। संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों की ओर से असहयोग और संबद्ध वस्तु के बारे में संगत आंकड़ों की उपलब्धता के अभाव को देखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाता है तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात उन्हीं कीमतों पर भारत में होने की संभावना है। इसके अलावा एस बी आर की क्षमताओं और उपर्युक्त पत्रिका में संबद्ध देशों में उसकी खपत की पद्धतियों के बारे में उपलब्ध आंकड़ों से इस बात की स्पष्ट संभावना बनती है कि इन अप्रयुक्त/बेशी क्षमताओं का उपयोग लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार अप्रयुक्त क्षमताएं मौजूद होने की स्थिति में यद्यपि, यह माना जाता है कि तीसरे देश को होने वाले निर्यात भारत में नहीं किए जाएंगे (संबद्ध देशों से तीसरे देश के बाजारों को संबद्ध वस्तु के निर्यातों के संबंध में संगत आंकड़ों के अभाव में) तथापि, पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की स्पष्ट संभावना बनी हुई है। तदनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर पाटन एवं पाटन मार्जिन की संभावना का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन जापान के संबंध में 323.55 अम.डॉ./मी.ट.; कोरिया गण. के संबंध में 393.38 अम.डॉ./मी.ट. तथा यू.एस ए के संबंध में 493.71 अम.डॉ./मी.ट. बनता है।

छ. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह एक पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा होने के नाते वास्तविक क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के वास्तविक और संभावित आयातों के संदर्भ में की जानी अपेक्षित है।

छ.1 क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

28. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोध संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

- (i) डब्ल्यू टी ओ नियमों में यह उल्लेख है कि लागू पाटनरोधी शुल्क उस समय तक प्रवृत्त रहना चाहिए जब तक उत्पाद पाटित कीमतों पर निर्यात किया जाता है और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहती है अथवा घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुनरावृत्ति होने की परिणामी संभावना के साथ शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। अतः क्षति पहुंचाने वाले पाटन का मुकाबला करने के लिए शुल्क को आवश्यक सीमा तक लागू रखना चाहिए।
- (ii) भारतीय नियमों में भी यह उल्लेख है कि लागू पाटनरोधी शुल्क तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी समीक्षा में इस मत में न पहुंचे कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है।
- (iii) नियम 11 के अनुसार निर्णायक समीक्षा जांच में घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच आवश्यक परिवर्तनों के साथ की जानी अपेक्षित होती है।
- (iv) जापान और कोरिया के निर्यातकों ने भारतीय बाजार में सामग्री को पाटन जारी रखा। यद्यपि आयातों की मात्रा कम है तथापि, उससे पाटित कीमतों का स्पष्ट पता चलता है।
- (v) आयातों की पहुंच कीमत जो घरेलू बिक्री कीमत से कम है, उसमें आगे और गिरावट आई है। अतः पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से कीमत में कटौती होगी।
- (vi) संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न्यूनतम निर्धारित सीमा से अधिक है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पूर्व में की गई जांच के बाद यद्यपि निर्यात कीमतों में वृद्धि हुई है, तथापि निर्यात कीमत में वृद्धि केवल रूपए में हुई है न कि अम.डॉ. में। निर्यातक के लिए वास्तविक वस्तुली (जिसे अम.डॉ. से जोड़ा जाता है) में गिरावट आई है। इसके अलावा, कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि होने के कारण विदेशी उत्पादकों की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है।
- (vii) इस अवधि में घरेलू उद्योग की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है क्योंकि बाजार में पाटित आयात उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, निम्नलिखित अनुरोधों से यह पता चलेगा कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुनरावृत्ति होगी।
- (viii) आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से हुए निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु से सीधे प्रतिस्पर्धा करते

हैं। अतः प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी निर्धारण करने का अनुरोध किया।

(ix) निर्यातक देशों में मुक्त रूप से निपटान योग्य पर्याप्त क्षमताएं मौजूद हैं। निर्यातक देशों में खपत उनकी स्थापित क्षमता से काफी कम है और इन देशों के निर्यातकों के पास अपनी बेशी क्षमता की बिक्री करने के लिए कुछ बाजारों की तलाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में इस चरण पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से देश में आयातों की भरमार हो जाएगी। इन विदेशी उत्पादकों के लिए भारतीय मांग की सीमा तक निर्यात करना कठिन नहीं होगा।

छ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. मै. पैरागन रबड इंड और मै. पैरागन पालीमर प्रोडक्स प्रा. लि. (आयातक) ने निम्नलिखित अनुरोध दायर किए हैं। क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई तर्क नहीं दिया है। मै. पैरागन रेबड इंड और मै. पैरागन पालीमर प्रोडक्ट्स प्रा. लि. ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि :

- (i) एप्कोटैस ने उचित कारण दिए बिना क्षति एवं कारणात्मक संबंध से संबंधित सूचना को अनावश्यक रूप से गोपनीय माना है। इसके अलावा, अगोपनीय सूचना के संबंध में कोई उचित सूचीकरण नहीं किया गया है। अतः ऐसी सूचना अस्वीकार्य है।
- (ii) सुनवाई के दौरान एप्कोटैक्स ने पाटन, क्षति-एवं कारणात्मक संबंध के बारे में अपने मामले में कोई अनुरोध नहीं किया था।
- (iii) एप्कोटैक्स ने अपने आवेदन में किसी क्षति का दावा नहीं किया है और उनके खुद के अनुरोध के अनुसार वैश्विक मंदी, खराब निष्पादन का कारण है। अतः पाटन एवं क्षति की संभावना की जांच करना प्राधिकारी का दायित्व है।
- (iv) यू.एस.ए से शुल्क जारी रखने का दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि उस देश से कोई आयात नहीं हुआ है और इस प्रकार किसी कारणात्मक संबंध की पुष्टि नहीं हुई है।
- (v) तीसरे देशों से भारत को हुए निर्यातों का कोई साक्ष्य, कीमत व्यवहार अथवा उनकी क्षमता, मांग, बिक्री अनुमान अथवा अन्य बाजारों में संभावित कीमत का कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है।
- (vi) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सार्वजनिक दस्तावेजों की पहुंच प्रदान नहीं की है। सार्वजनिक फाइल का उचित रखरखाव नहीं है।
- (vii) पहुंच मूल्य की गणना त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अपवर्जित उत्पादों के आंकड़े भी शामिल किए गए हैं।
- (viii) निर्दिष्ट प्राधिकारी को एप्कोटैक्स द्वारा प्रश्नावली का उत्तर दायर करने के लिए भरोसा किए गए आंकड़ों, एप्कोटैक्स और अन्य पक्षकारों के बीच हुए पत्राचार का अगोपनीय रूपांतरण, टी/टी डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों और अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों, स्टायलिन मोनोमर तथा बूटाडिन हेतु डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों, सामान्य मूल्य की गणना हेतु कार्य पद्धति, यू.एस.ए की विद्युत दरे लिए

जाने के आधार, निर्यात कीमत की गणना करने के लिए समायोजनों का साक्ष्य तथा अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री के स्रोत, संबद्ध देशों के उत्पादकों की क्षमताओं के साक्ष्य को उपलब्ध कराना चाहिए ।

- (ix) सी आई एफ कीमत की गलत गणना की गई है ।
- (x) वर्ष 2005-06 के लिए प्रविष्टियां दोहराई गई हैं ।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

30. प्राधिकारी ने क्षति की जांच से संबंधित तर्कों को नोट किया है और उठाए गए मुद्दों पर उचित स्थानों पर विचार किया है । प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की तथ्यपरक जांच की है ।

31. यह उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक फाइल का विधिवत रखरखाव किया गया है और वह पारस्परिक सुविधा के अनुसार समय-समय समस्त हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई है ।

32. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ॥ में यह उपबंध है कि क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव ; तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।

33. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-॥ के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है ।

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमत, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित त्रह्णात्मक प्रभावों का मूल्यांकन शामिल होगा ।"

छ.3.1. क्षति जारी रहने की संभावना

34. प्राधिकारी ने सर्वप्रथम इस बात की जांच की है कि क्या जांच अवधि के दौरान निष्पादन के आधार पर घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने की संभावना है।

35. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के मात्रात्मक एवं कीमत प्रभाव तथा कीमत एवं लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, की मौजूदगी की जांच की जा सके।

मात्रात्मक प्रभाव

(क) मांग का निर्धारण

36. संबद्ध वस्तु की घरेलू खपत/मांग का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग तथा अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री मात्रा को भारत में हुए कुल आयातों में जोड़ा गया है जिसका संक्षेप में व्यौरा निम्नानुसार है:

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
संबद्ध देशों से आयात					
जापान	मी.ट.	86	248	26	29
कोरिया गण.		-	-	-	-
अमरीका		-	-	-	-
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	50	7	-	33
कुल आयात	मी.ट.	136	255	26	61
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	4473	3742	6794	4531
अन्य भारतीय उद्योग की बिक्री	मी.ट.	4752	4090	7116	4463
कुल मांग	मी.ट.	9,361	8,087	13,936	9,055

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यद्यपि, आधार वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान उत्पाद की मांग में गिरावट आई है। इन वर्षों में संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में भी गिरावट आई है और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में मामूली वृद्धि हुई है।

(ख) आयात की मात्रा और बाजार हिस्सा

37. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) में यह उपबंध है कि "पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है ... ।" इस प्रकार पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों ने समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

38. निम्नलिखित तालिका में आयात की मात्रा और बाजार हिस्से की संक्षिप्त स्थिति दी गई है:-

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
संबद्ध देशों से आयात					
जापान	मी.ट.	86	248	26	29
कोरिया गण.	मी.ट.	-	-	-	-
अमरीका		-	-	-	-
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	50	7	-	32
कुल आयात	मी.ट.	136	255	26	61
भारतीय उत्पादन	मी.ट.				
मांग	मी.ट.	9,361	8,087	13,936	9,055
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
कुल आयात	%	63.58	97.12	100.00	46.91
उत्पादन	%	1.96	6.54	0.38	0.61
खपत	%	0.92	3.07	0.19	0.32
मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	47.48	46.27	48.75	50.04

उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- (i) वर्ष 2007-08 की अवधि को छोड़कर सबद्ध वस्तु की मांग 9361 से 9055 के बीच रही है । घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि प्राकृतिक रबड़ की कीमत में वृद्धि होने वर्ष 2007-08 में मांग में वृद्धि हुई थी जिससे प्राकृतिक रबड़ के स्थान पर विचाराधीन उत्पाद का उपयोग हुआ है ।
- (ii) जहां तक जांच अवधि में संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों की नगण्य मात्रा का संबंध है, आधार वर्ष की तुलना में संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में भी गिरावट आई है । यू एस ए और कोरिया गण. से कोई आयात नहीं हुए हैं । यद्यपि, जापान से हुए आयात की मात्रा पर्याप्त नहीं है ।

छ.3.2 घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों का कीमत प्रभाव

39. घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के कीमत प्रभाव का पता लगाने के लिए प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाठित आयातों के कारण कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा पर्याप्त स्तर तक गिरावट आई है अथवा होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती है।

40. कीमत कटौती की मात्रा का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की है। निवल बिक्री प्राप्ति की गणना समस्त रिबेटों और करों को हटाने के बाद की गई है। आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना लागू पाटनरोधी शुल्क पर विचार करने के बाद भी घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ की गई है और यह नोट किया जाता है कि लागू सीमाशुल्क सहित संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से काफी कम है।

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	107	134
पहुंच मूल्य	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	106	111	102
पाटनरोधी शुल्क बैंचमार्क	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	103	92	103
कीमत कटौती राशि	रु./मी.ट.	(***)	(***)	(***)	***
प्रवृत्ति		(100)	(100)	(128)	36
कीमत कटौती %	%	(***)	(***)	(***)	***
प्रवृत्ति		(100)	(93)	(120)	27

कीमत हास/न्यूनीकरण

41. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या संबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत का हास/न्यूनीकरण हुआ है, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत के साथ-साथ उत्पादन लागत तथा घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना की है जिसका उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है:

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
उत्पादन की लागत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	97	113
निवल बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	105	134
लाभ/हानि	रु./मी.ट.	(***)	(***)	(***)	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(178)	(31)	39

प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन लागत और निवल बिक्री प्राप्ति में वर्ष 2006-07 में वृद्धि हुई और 2007-08 में गिरावट आई और जांच अवधि में पुनः वृद्धि हुई । घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि यह वृद्धि निविटि लागत में वैष्विक वृद्धि के कारण हुई थी । प्राधिकारी ने स्पष्ट तौर पर उत्पादन लागत में वृद्धि के साथ-साथ कीमत में उचित वृद्धि की थी । तथापि, इसे इस परिप्रेक्ष्य में देखना अपेक्षित है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है । अतः इस बात की आगे और जांच करने की जरूरत है कि क्या लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने पर स्थिति ऐसी ही रहने की संभावना है ।

घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

42. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के विश्लेषण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा ।

उत्पादन, बिक्री, क्षमता तथा क्षमता उपयोग

43. घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री, क्षमता एवं क्षमता उपयोग निम्नानुसार है:

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	(जांच अवधि)
क्षमता	मी.ट.	10,000	10,000	10,000	10,000

उत्पादन	मी.ट.	4,405	3,792	6,967	4,726
क्षमता उपयोग	%	44.05	37.92	69.67	47.26
घरेलू बिक्री	मी.ट.	4,449	3,742	6,794	4,531
मांग	मी.ट.	9,361	8,087	13,936	9,055
मांग का उत्पादन % में	%	47.06	46.89	49.99	52.19
मांग की बिक्री % में	%	47.53	46.27	48.75	50.04

यह नोट किया जाता है कि उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन मांग के अनुसार रहा है । तथापि, घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रतिकूल बन जाएगा क्योंकि (क) संबद्ध देशों में अतिरिक्त क्षमता है; (ख) भारत में व्यापक घरेलू बाजार है और (ग) भारतीय बाजार की कीमत आकर्षक है जैसा कि जांच अवधि के दौरान कीमत में अत्यधिक कटौती की मौजूदगी से स्पष्ट हो जाएगा ।

लाभप्रदता

44. घरेलू उद्योग उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति तथा लाभ/हानि का उल्लेख निम्नानुसार है:

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
उत्पादन की लागत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	116	97	113
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	108	105	134
लाभ/हानि	रु./मी.ट.	(***)	(***)	(***)	***
प्रवृत्ति	रु./मी.ट.	(100)	(178)	(31)	39

प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है और उसने जांच अवधि में लाभ कमाना शुरू कर दिया है ।

बाजार हिस्सा

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
संबद्ध देश					
जापान	%	0.92	3.07	0.19	0.32
कोरिया गण					
अमरीका					
अन्य देश	%	0.53	0.09	-	0.36
घरेलू उद्योग	%	47.78	46.27	48.75	50.03
अन्य घरेलू उत्पादक	%	50.77	50.57	51.06	49.29

घरेलू उत्पादकों की बिक्री और संबद्ध देशों से हुए आयातों की तुलना से यह पता चलता है कि आयात की मात्रा कम रही है जो पाटनरोधी शुल्क की वजह से हो सकती है । तथापि, यदि वर्तमान शुल्क समाप्त किया जाता है तो इस बात की आगे और जांच अपेक्षित होगी कि क्या पाटित आयातों, यदि कोई हो, की मौजूदगी के कारण कीमत में भारी अंतर को देखते हुए घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अथवा बाजार हिस्से में गिरावट आने की संभावना है ।

रोजगार और मजदूरी

45 रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित स्थिति निम्नानुसार है:

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	99	111	104
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	106	132	158
प्रति दिवस उत्पादकता	मी. टन/दिवस	12.24	10.53	19.35	13.13

प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में स्पष्टतः गिरावट नहीं आई है ।

46. निवेश पर आय और नकद प्रवाह

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
आर ओ आई - जी एफ ए आधार	%	(***)	(***)	(***)	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(142)	(37)	46
आर ओ आई- एन एफ ए आधार	%	(***)	(***)	(***)	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(144)	(36)	58
नकद लाभ	लाख रुपए	(***)	(***)	(***)	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(201)	(32)	140

प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात मात्रा में गिरावट आने के कारण निवेश पर आय में सुधार हुआ है। जांच अवधि के दौरान भारतीय बाजार में आयातों की कोई खास मात्रा न आने के कारण निवेश पर आय तथा नकद लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन सकारात्मक बन गया है। तथापि, संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य और निवल बिक्री प्राप्ति तथा घरेलू उद्योग की क्षितिरहित कीमत के बीच कीमत में वर्तमान अंतर के कारण इस बात की आगे जांच करना अपेक्षित है कि क्या लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

47. मालसूची

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
औसत मालसूची	मी.ट.	212	127	92	109

यह देखा जाता है कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान मांग में आई गिरावट के कारण हुई है। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में मालसूची में गिरावट आई है।

घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी और इसमें मालसूची का स्तर भी शामिल होगा।

48. पूंजी जुटाने की क्षमता

प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग कई प्रचालन नहीं करता है और उत्पाद के निष्पादन पर किसी प्रतिकूल प्रभाव से पूंजी जुटाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

पाटन मार्जिन की मात्रा

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा अधिक नहीं रही है परंतु जांच अवधि के दौरान किए गए आयात की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा होने के कारण पाटन मार्जिन काफी अधिक रहा है। जांच अवधि में पाटन मार्जिन भी इन देशों के निर्यातकों के संभावित भावी व्यवहार का संकेत है।

वृद्धि

50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिकांश मापदंडों के संबंध में वृद्धि सकारात्मक रही है परंतु इस बात की आगे जांच करना अपेक्षित है कि क्या लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने पर घरेलू उद्योग का निष्पादन उसी ढंग से जारी रहेगा।

क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

51. प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की क्षतिरहित कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु संबद्ध देशों से हुए निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। इस प्रकार की तुलना से पाटन मार्जिन निम्नानुसार बनता है:

निवल निर्यात कीमत	रु./मी.ट.	***
पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	***
क्षति मार्जिन	रु./मी.ट.	***
क्षति मार्जिन (%)	%	
प्रवृत्ति	%	10 - 15

क्षति की पुनरावृति की संभावनाघरेलू उद्योग के अनुरोध

घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि:

- संबद्ध देशों के निर्यातक/उत्पादकों द्वारा संबद्ध देशों में अतिरिक्त क्षमताओं के कारण भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किए जाने की संभावना है।
- किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और सहयोग नहीं किया है जिससे वे यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन तथा परिणामी क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है।
- घरेलू और आयातित सामग्री के बीच कीमत में भारी अंतर है और इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में

खासकर तब जब विदेशी उत्पादकों के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताएं मौजूद हैं, भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का निर्यात पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जाएगा ।

- निर्यातकों ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और पाटन का मुकाबला करने के लिए शुल्क को निरंतर लागू रखना अनावश्यक है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

53. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यद्यपि, घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की अल्प मात्रा के कारण जांच अवधि के दौरान क्षति नहीं हुई है, तथापि, इस बात की आगे जांच की गई है कि लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन एवं परिणामी क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

54. हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और अनुरोधों की जांच की गई है और प्राधिकारी की जानकारी में लाए गए ऐसे सभी कारकों का मूल्यांकन किया गया है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है । इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित क्षमता, उत्पादन, आयातों के पहुंच मूल्य, संबद्ध देशों में बेशी क्षमता, निर्यात की संभावना, घरेलू मांग, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति तथा क्षति रहित कीमत जैसे मापदंडों पर विचार किया गया है ।

55. प्राधिकारी ने नोट किया है कि लाभ शुल्क की मौजूदगी के बावजूद पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का आयात (यद्यपि अल्प मात्रा में) किया गया है । इस बात की संभावना है कि इस जांच परिणाम के संगत खंड में पहले से किए गए उल्लेख के अनुसार पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से उसी कीमत पर संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जा सकता है ।

56. अतः प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होने की स्थिति में क्षति होने की संभावना की आगे जांच की है । यह नोट किया गया है कि पाटित कीमतों पर जांच अवधि के दौरान अल्प मात्रा (परंतु वाणिज्यिक मात्रा) में आयात किए गए हैं । किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर इस जांच में सहयोग नहीं किया है । यद्यपि, घरेलू उद्योग ने आई आई एस आर पी की वर्ल्ड रबड स्टेटिक्स, 2008 की रिपोर्ट के आधार पर (इस उत्पाद से संबंधित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका जिसमें विभिन्न वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के पास उपलब्ध क्षमताओं और देश वार खपत की पद्धति के बौरे उपलब्ध हैं) निर्यातक देशों में संबद्ध वस्तु की क्षमता, उत्पादन और मांग से संबंधि सूचना उपलब्ध कराई है । रिपोर्ट के अवलोकन से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों में एस बी आर के विनिर्माण हेतु बेशी क्षमताएं हैं जिसमें संबद्ध वस्तु भी शामिल है । इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि कुछेक वैश्विक उत्पादकों द्वारा वस्तुतः एस बी आर के अलग-अलग प्रकारों का उत्पादन करने हेतु उत्पादन सुविधाओं का अदल-बदल कर उपयोग किया जाता है ।

57. असहयोग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी के पास रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर क्षति की संभावना का निर्धारण करने के अलावा विकल्प अत्यंत कम हैं । यह देखा

गया है कि जांच अवधि के दौरान आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति और क्षति रहित कीमत से काफी कम रहा है। इस बात का अनुमान लगाते हुए कि कीमत प्रवृत्ति एक जैसी रही है, इस बात की संभावना है कि संबद्ध वस्तु के पाटन की पुनरावृत्ति होने के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

58. इसके अलावा, यह पाया गया है कि संबद्ध देशों द्वारा कई देशों को निर्यात किया जा रहा है और इसलिए तीसरे देशों को किए जाने वाले निर्यातों को भारत में भेजने की संभावना से इंकार नहीं किया जाता है।

तालिका

देश	2008 ('000 मी.ट.)						
	क्षमता	मांग	बेशी क्षमता	निर्यातक	आयातक	व्युत्पत्ति उत्पादन	उपलब्ध बेशी क्षमता
जापान	564	416	148	148	98	466	246
अमरीका	1,125	767	358	313	278	802	636
कोरिया गण	516	229	287	453	31	651	318
भारत*	17	9	8	0	0	9	8

स्रोत : आई आई एस आर पी - वर्ल्ड रबड स्टेटिक्स, 2008, अनकामट्रेड के निर्यात-आयात आंकड़े

- भारतीय आंकड़े केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए हैं और अन्य देश के आंकड़े समग्र एस बी आर के लिए हैं।

59. इस बात पर विचार करते हुए कि देश में संबद्ध वस्तु की काफी मांग है और यह कि संबद्ध देशों में अपना उत्पादन बढ़ाने और निर्यात मात्रा को जुटाने की संभावना है, पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से कीमत की वजह से संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों के लिए भारतीय बाजार के आकर्षक बनने की संभावना है। ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना है कि संबद्ध वस्तु के आयात उस कीमत पर किए जा रहे हैं जिस कीमत पर उसका आयात जांच अवधि के दौरान किया गया है (भले ही उसकी मात्रा कम रही हो)। ऐसा अनुमान लगाते हुए यह मामला कीमत में अत्यधिक कटौती और अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री का बनने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव बन सकता है।

60. इसके अलावा, पाटन एवं पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना को ध्यान में रखते हुए इन देशों के निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा कीमत को कम किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों के ऐसे कीमत व्यवहार के साथ-साथ संबद्ध वस्तु की पर्याप्त क्षमताएं भेजने की उनकी क्षमता के कारण कीमत संवदनशील घरेलू बाजार पर कीमत हासकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ज. कारणात्मक संबंध

61. प्राधिकारी ने निर्णयिक समीक्षा जांच में कारणात्मक संबंध के महत्व और प्रासंगिकता से संबंधित अनुरोधों की जांच की है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 9 (5) के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए पाटन एवं क्षति की संभावना और शुल्क जारी रखने की जरूरत की जांच करना अपेक्षित होता है भले ही समीक्षा जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात किया गया हो अथवा नहीं। तथापि, इस बात की जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी नियमावली में सूचीबद्ध अन्य मापदंडों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। निम्नानुसार नोट किया जाता है :

अन्य देशों से मूल्य तथा कीमतें

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से आयात की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथापि, घरेलू उद्योग को यह क्षति इस मात्रा के कारण नहीं हुई है क्योंकि अन्य देशों से आयात की कीमत काफी अधिक है।

मांग में कमी और/अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

63. यह नोट किया जाता है कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि प्राकृतिक रबड़ की कीमत में वृद्धि होने के कारण वर्ष 2007-08 में मांग में वृद्धि हुई थी जिसकी वजह से प्राकृतिक रबड़ के स्थान पर विचाराधीन उत्पाद का उपयोग किया गया था। इसका खंडन किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने नहीं किया है। अतः यह देखा जाता है कि खपत की पद्धति में किसी परिवर्तन का कोई संकेत नहीं है।

विदेशी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

64. संबद्ध वस्तु का आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होता है और वह देश में मुक्त रूप से आयात के योग्य है। घरेलू उत्पादक एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और साथ ही साथ संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत से प्रतिस्पर्धा करते हैं। घरेलू उद्योग की कीमत संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत से अत्यधिक प्रभावित होती है। इसके अलावा, किसी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह पता चल सके कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है।

प्रौद्योगिकी विकास

65. न तो किसी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारण के रूप में प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित कोई मुद्दा उठाया है और न ही प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई खास विकास प्रतीत होता है जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति का प्रमुख कारण बन सकता है।

निर्यात निष्पादन

66. घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु का मामूली निर्यात किया गया है। प्राधिकारी ने हर हालत में घरेलू प्रचालनों के संबंध में लाभप्रदता और अन्य कीमत मापदंडों पर भी विचार किया है।

उत्पादकता

67. यह नोट किया जाता है कि पाटन के अभाव में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रभावित नहीं हुई है।

68. अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अन्य सूचीबद्ध ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

69. इस बात का निर्धारण करने में कि क्या उत्पाद के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया है:

(क) आयात अभी भी पाटित कीमतों पर हो रहे हैं। यद्यपि, पाटित आयातों की मात्रा कम बनी हुई है जिसकी वजह पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी को माना जा सकता है। इस बात की जांच की जाएगी कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में क्या संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि होगी और क्या इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को अपना बाजार हिस्सा गंवाए जाने की संभावना है।

(ख) घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कमोबेश स्थिर रहा है। तथापि, यह देखा जाएगा कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होने से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पी कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ग) क्या संबद्ध वस्तु के आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होने की संभावना है।

(घ) घरेलू उद्योग के लाभ/लगाई गई पूंजी पर आय तथा नकद लाभ में सुधार हुआ है जो पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण हो सकता है। अतः आगे यह देखा जाएगा कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होने से इन मापदंडों पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ङ) अनेक मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि में सकारात्मक सुधार प्रदर्शित हुआ है जो लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण हो सकता है। अतः आगे यह देखा जाएगा कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होने से इन मापदंडों पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है।

झ. निष्कर्ष

70. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदत्त सूचना और किए गए अनुरोधों तथा उपर्युक्त जांच परिणाम में दर्ज प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन की पुनरावृत्ति और परिणामी क्षति होने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

- (i) लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध वस्तु के भारतीय बाजार में पाटित कीमत पर प्रवेश किए जाने की संभावना है ।
- (ii) लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग की स्थिति खराब होने की संभावना है ।
- (iii) घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण आने की संभावना है ।
- (iv) अतः पाटनरोधी शुल्क की अवधि को बढ़ाया जाना अपेक्षित है ।

ट. सिफारिशें

71. इस आशय का निष्कर्ष निकालने के बाद की लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध वस्तु का निर्यात पाटित कीमतों पर किए जाने की संभावना है और पाटन एवं घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है । अतः प्राधिकारी का यह भत है कि इस उपाय की अवधि में निम्नलिखित शुल्क तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार विस्तार किया जाना अपेक्षित है ।

72. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति की संभवना को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क को सतत रूप से लगाने की सिफारिश करते हैं । तदनुसार संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समस्त आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित तालिका के कॉलम 8 में उल्लिखित राशि के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है ।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/उप-शीर्ष	वस्तु का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	4002.19	1900 शृंखला का स्टाइरिन बूटाडिन रबड	कोरिया गण.	ऐसे देश से इतर कोई देश जिस पर पाटनरोधी	कोई	कोई	0.0689	प्रति किग्रा.	अम.डॉ.

				शुल्क लागू है					
2	4002.19	1900 श्रृंखला का स्टाइरिन बूटाडिन रबड	ऐसे देश से इतर कोई देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	कोरिया गण.	कोई	कोई	0.0689	प्रति किग्रा.	अम. डॉ.
3.	4002.19	1900 श्रृंखला का स्टाइरिन बूटाडिन रबड	जापान	ऐसे देश से इतर कोई देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	कोई	कोई	0.1045	प्रति किग्रा.	अम. डॉ.
4.	4002.19	1900 श्रृंखला का स्टाइरिन बूटाडिन रबड	ऐसे देश से इतर कोई देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	जापान	कोई	कोई	0.1045	प्रति किग्रा.	अम. डॉ.
5.	4002.19	1900 श्रृंखला का स्टाइरिन बूटाडिन रबड	अमरीका	ऐसे देश से इतर कोई देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	कोई	कोई	0.197	प्रति किग्रा.	अम. डॉ.
6.	4002.19	1900 श्रृंखला का स्टाइरिन बूटाडिन रबड	ऐसे देश से इतर कोई देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	अमरीका	कोई	कोई	0.197	प्रति किग्रा.	अम. डॉ.

73. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3,3, 8 T, 9 और 9 के अंतर्गत लागू शुल्क को छोड़कर सभी सीमाशुल्क शामिल हैं;

74. इस आदेश के खिलाफ कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2010

Final Findings

Subject : Sunset Review of Anti-dumping duties imposed on imports of Styrene Butadiene Rubber (SBR) 1900 series originating in or exported from Japan, Korea RP and USA.

F. No. 15/25/2008-DGAD.—A.1 Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules), the definitive anti-dumping duty was originally imposed vide notification No.107/1999-Customs, dated the 24th August, 1999 on import of Styrene Butadiene Rubber (SBR) originating in or exported from Japan, Taiwan, Turkey, Taiwan, France, USA, Germany and Korea RP.

2. And whereas, the Designated Authority vide its notification No 34/1/2000-DGAD, dated 3rd July, 2001 in the Mid-term review had recommended the continuation of anti- dumping duty on imports of Styrene Butadiene Rubber (SBR) originating in or exported from Japan, Korea, USA, Turkey and Taiwan vide Customs Notification No. 56/2002 dated 31/05/2002.

3. And whereas, the Designated Authority vide its notification No 15/5/2003-DGAD, dated 27th July, 2004 in the Sunset review had recommended the continuation of anti-dumping duty on imports of Styrene Butadiene Rubber (SBR) 1900 series, (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from Japan, Korea RP and U.S.A., (hereinafter also referred to as the subject countries). Accordingly, the anti-dumping duties were extended vide Customs Notification No. 100/2004 dated 28th September 2004 in terms of Section 9(A)(5) of the Act.

4. And whereas, in view of the order of the Hon'ble Delhi High Court in the matter of Indian Metal and Ferro Alloys Ltd v/s Designated Authority, Writ Petition (Civil) No. 16893 of 2006 and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of AD Rules, the Authority issued a public notice dated 31st March 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the sunset review investigation to review the need for continued imposition of duties in force and to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

5. And whereas, the antidumping duties as notified vide Notification No. 100/2004 dated 28th September, 2004 were extended up to 27th June, 2010 vide Customs notification No. 120/2009 dated 16th October 2009 in terms of Section 9(A)(5) of the Act.

B. PROCEDURE

6. In this proceeding, the procedure described herein-below has been followed:

- i. The Embassies of Japan, Korea RP and USA in India were informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules.
- ii. The Designated Authority sent copies of the initiation notification dated 31st March 2009 to the Embassies of Japan, Korea RP and USA in India, known exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, and the domestic industry, as per the information available with it. Parties to this investigation were requested to file the questionnaires' responses and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to the Embassies of Japan, Korea RP and USA in India along with a list of known exporters / producers with a request to advise the exporters/ producers from the subject countries to respond to the questionnaires within the prescribed time.
- iii. Questionnaires were sent to the following known exporters from the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules to elicit relevant information:

S.N.	Company's Name
1.	M/s Ameripol Synpol Company, USA.
2.	M/s Korea Kumho Petrochemical Co. Ltd, Seoul, Korea.
3.	M/s Nippon Zeon Company Ltd., Japan.
4.	M/s JSR Corporation, Japan.

None of the exporter/producer from the subject countries has filed the questionnaire's response. However, M/s Korea Kumho Petrochemical Co. Ltd., Korea, has made submissions in response to the above notification.

- iv. M/s Apcotex Industries Ltd., a major domestic producer of the subject goods filed their submissions and has pleaded for the continuation of the anti-dumping duties in the instant matter.
- v. Questionnaires were sent to the following known importers, users and associations of the subject goods in India for seeking the necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

S.N.	Company's Name
1.	Paragon Rubber Industries, Kerala
2.	Texim International, Madhavaram, Madras
3.	Bykoff Rubber Inds, Kerala

4.	Malaya Trade Impex P.Ltd., Kerala
5.	Josco Rubbers, Calicut
6.	Paragon Polymer Products P. Ltd., Salem
7.	Leader Rubber Inds, Calicut, Kerala
8.	Veeksay Rubber Inds, , Kerala
9.	Safar Rubbers, Mallappuram,
10.	Kerala Footwear Products, Calicut, Kerala
11.	Arihant Rubber & Chemicals, Calcutta
12.	Chemi Colour Agency, Calcutta
13.	Viking Rubbers P Ltd., Kerala
14.	Bombay Pigments & Allied Products, Kerala
15.	Neo Rubber Foot Crafts P Ltd., Kerala
16.	Footcare Rubber Inds,, Kerala
17.	Preston India P. Ltd., Bangalore
18.	Maharashtra Trading Corporation, Mumbai -3
19.	All India Rubber Industries Association, Northern Region, New-Delhi

In response to the above notification, M/s Paragon Rubber Industries and M/s Paragon Polymer Products Pvt. Ltd. have filed their importer's questionnaire responses. However, Rishiroop Polymers Pvt. Ltd. Mumbai has filed their submissions in response to the initiation notification.

- vi. The imports data for the period of investigation and proceeding three years was called from Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S).
- vii. The Authority made available non-confidential version of the information/data and evidence presented by the interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

viii. The Authority examined the information furnished by M/s Apcotex Industries Ltd., to the extent possible on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) to analyze the injury suffered and to work out the cost of production, cost to make and sell the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

ix. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided an opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 25th February 2010. The parties which presented their views in the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered, wherever found relevant, in these findings.

x. The period of investigation for the purpose of the present review is April 2008 – March 2009 (12 months POI). However, the injury analysis covers the periods 2005-06, 2006-07, 2007-08 and the POI.

xi. In accordance with the Rule 16 of the AD Rules, the essential facts under consideration before the Authority in the instant matter were disclosed to the known interested parties. The comments received on the disclosure statement have been duly considered in these findings.

xii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xiii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the 'facts available'.

xiv. *** In this statement represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules.

C. Comments on the Disclosure statement

7 (a) Submissions on behalf of M/s Paragon Polymer Products Pvt Ltd and M/s Paragon Rubber Industries:

The following comments, in brief, have been made:

- The submissions made earlier by them may be taken as a part of these comments.
- Standing: Details submissions were made to point out that no mandatory certifications were attached with the application and the effect of such deficiency on the

investigations. The Hon'ble Authority has ignored the submission that there was no mandatory certification filed stating that there were no self import and no relationship with exporters or importers of product under consideration. In view thereof, it cannot be said that the application is filed for and on behalf of Domestic Industry as defined. Further, the certification about the information being true and correct has also not been filed.

- Applicants relationship with Exporters or Importers: The submissions under this heading have been totally ~~been~~ ignored. In view thereof, it cannot be said that Designated Authority has carried out the mandatory tests to examine whether they could have entertained the questionnaire response as having been filed for and on behalf of Domestic Industry. No examination has been undertaken by the Designated Authority in terms of later part of Rule 2(b) in view of absence of declarations made and certificates given by the applicant industry. To that extent no examination has been undertaken to reach a conclusion that the application can at all be treated as having been filed for and on behalf of "Domestic Industry" as defined.
- Confidentiality: The issue of confidentiality was brought forth to the Hon'ble Authority in our earlier submissions also. The documents provided to us also were in the indexed form and did not reveal the full and proper information as required under the Anti-dumping Rules. Thus, in the absence of proper non-confidential version of the documents, we were unable to offer any meaningful comments on the same.
- Computation of Normal Value & NIP: It is respectfully submitted that the disclosure statement is inadequate inasmuch as it does not reveal even the methodology of computation of normal value, export price, dumping margin and the NIP. Further, we have not been provided with Annexure 4 of the disclosure statement.
- Incomplete Public File: It is submitted that the public file does not contain the non-confidential versions of the correspondence exchanged, non-confidential versions of every document given to the Designated Authority on confidential basis and verification reports for the domestic industry. The data obtained from DGCI&S was also not placed in the public file.
- Product under consideration: M/s Apcotex has referred to subject goods as High Styrene Resin (HSR). We would request, the Designated Authority not to alter the definition of product under consideration in any manner for the purpose of present sunset review investigation. We also pray that the scope cannot be enhanced to include KHS 68 which has been categorically been excluded earlier specifically in a situation when such exclusion has merged with the order of the Hon'ble Supreme Court in Rishiroop Polymers case. The Designated Authority could not have restored its own order on product under consideration which stood merged and changed in terms of Supreme Court order.
- Likelihood Analysis Flawed: We are constrained to reiterate that in a sunset review investigation the likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury is required to be adjudged in case anti-dumping duties are withdrawn. In the disclosure statement, there is no analysis of this most crucial aspect of likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty. Admittedly there is no injury during the current period of investigation. It may also be noted that while examining likelihood of recurrence of injury and dumping, the following factors are material for making determinations in a sunset review investigation:
 - a) Availability of disposable and unused capacities of the exporters in the subject countries.

- b) The exporters from the subject countries are engaged in supplying the subject goods at lower prices to other countries indicating a likelihood of recurrence of dumping.
- c) Higher level of consumption of goods from the subject countries in the Indian market.
- d) That the exporters were not able to find new market to replace their sales and there is a likelihood of their goods to be dumped into India.

In the present case, in its questionnaire response M/s Apcotex under the heading "Conclusions on injury" has stated as under:

"Domestic Industry submits that the facts and circumstances of the present case are such that.....

- b. The volume of imports in the current period were low. Consequently, the domestic industry has not suffered continued injury.***
- c. With the significant decline in the global prices, the Domestic Industry was forced to reduce its prices after Sept. 2008. The price decline continues significantly till March 09.***
- d. With the significant decline in demand for the product, the Domestic Industry faced significant decline in sales volume and consequently production & capacity utilization.***
- e. In the event of revocation"*** (Emphasis added)

The above extract from the response of M/s Apcotex clearly goes to show that no injury is claimed in the questionnaire response. Reduction in prices and decline in production and capacity utilisation is attributed to global prices reduction and decline in demand. In such a situation, Designated Authority is therefore required to examine whether the cessation / discontinuance of anti-dumping duties in force is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury.

- The likelihood analysis is flawed and is based on extraneous considerations and data that does not relate to product under consideration. The conclusions on surplus capacities are also not based on data relating to product under consideration and hence flawed.
- Causal link: The causal link analysis is also flawed as admitted facts do go to show that demand had declined. No impact analysis had been undertaken to examine its impact on the applicant. Despite such admission regarding contraction in demand, it has been recorded that there is no indication of any change in the consumption pattern. The decline in demand is only due to change in consumption pattern.

(b) Submissions by domestic industry:

The following comments, in brief, have been made:

- i In response to the disclosure statement, the domestic industry has disputed the proposed determination by the Authority that KHS-68 is not included within the scope of the product under consideration. While reiterating the earlier submissions in this regard, the domestic industry has argued that even when

the submissions made by them have not been disputed by the exporter, the exporter has consistently misled the Authority, available material clearly establishes that KHS-68 is SBR Elastomer Resin, the decision of the Hon'ble Supreme Court does not prevent the Authority from reviewing the previous order for modification; the Authority has rejected their claims/submissions, that too without giving any reasons.

ii With regard to other aspects of the investigation, the domestic industry is in agreement with the proposed determination of the Authority and has argued that the facts of the case clearly establishes continuation or likelihood of dumping and injury to the domestic industry and the anti-dumping duties are required to be extended further.

(c) Submissions on behalf of M/s Kumho Petrochemicals Ltd, Korea (Exporter) and M/s Rishiroop Polymers Ltd (Importer):

i It is submitted that in the original investigation the Authority never held that the PUC constituted of all types of SBR classified under Chapter 3903.90. On the contrary, the Authority expressly noted that the synthetic rubbers or articles thereof which are covered under Chapter 40 do not fall under chapter 39. The said Final Findings dated 21.06.99 was challenged by one interested party before the Hon'ble CEGAT, New Delhi. The Tribunal, in its wisdom, had upset the Final Findings vide its order dated 02.02.2000 holding that that Anti-dumping duty is on all grades of SBR, whether falling under sub-heading 4002 or 3903. Pursuant to the order of the Tribunal, the Authority had broadened the scope the product under consideration in the two intervening reviews i.e. Mid-term Review-I and Sunset Review-I. On appeal, however, the Hon'ble Supreme Court vide its decision dated 23.03.06 restored the order of the Authority in the original investigation.

ii Thus, pursuant to the decision of the Hon'ble Supreme Court, the Findings with respect to the product under consideration of the Authority in the original investigation stand as good law today. The Authority having determined that the items falling under sub-heading 3903.90 was beyond the scope of product under consideration for the purpose of imposing antidumping duty cannot modify the same in the present investigation. Further, the Authority had expressly noted "that the item cleared under chapter 39 was "Elastomer Resin KHS 68" and thus it was not under the nomenclature of "Synthetic Rubber". This was ratified by the Hon'ble Supreme Court noting that the finding recorded by the Designated Authority was categorical and not a clerical omission.

iii In the light of the above, it is submitted the Authority may record specifically the following with regard to the scope of the product under consideration:

It is observed that the product under investigation in the original investigation was all grades of Styrene Butadiene Rubber (SBR) classified under customs heading no. 4002.19 of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from Japan, Korea RP and USA. The original investigation concluded vide notification dated 2/6/99 recommended duty on SBR 1500, 1700 & 1900 series. However, the scope of duty was restricted to SBR 1900 series vide mid-term review

notification dated 3rd July 2001 and was retained so in the first sunset review investigation. Taking into account the above and also the decision of the Honorable Supreme Court in the case of *Rishiroop Polymers P. Ltd. v Designated Authority & Addl. Secretary*, 2006 (196) ELT 129, the product under investigation in this sunset review investigation is held to cover all grades of Styrene Butadiene Rubber (SBR) 1900 series classified under customs heading No.4002.19 of the Customs Tariff Act 1975 and does not include "Elastomer Resin KHS 68" as the same is not under the nomenclature of "Synthetic Rubber" classified under chapter 40.

(d) Examination by Authority

- As regards 'Standing' related issues, the Authority is of the view that the issues are not relevant as this SSR investigation was initiated on *suo-motto* basis.
- As regards 'Confidentiality' related issues, the Authority has treated the information provided by the interested parties on confidential basis on being satisfied with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide non-confidential version of the information filed on confidential basis
- As regards 'Product under Consideration' related issues, the Authority notes that the present investigation is the Sunset Review investigation and therefore the final findings earlier notified by the Authority and decision of the Hon'ble Supreme Court are binding with regard to the scope of the present investigation. Accordingly, the Authority confirms the disclosure statement and holds that the scope of the investigation does not include KHS-68.
- As regards 'Likelihood Analysis', it has already been clarified that the same is based on best information available on record and is fully consistent with Rule 6(8) of the AD Rules.
- All other issues that have been raised have been appropriately dealt with in relevant section of these findings.

Product under Consideration and Like Article

D. Submissions made by Domestic industry

8. M/s Apcotex Industries Ltd. has made the following submissions:

(i) The product under investigation in the original investigation was all grades of Styrene Butadiene Rubber (SBR) of 1500, 1700 and 1900 series. The scope of duty was restricted to SBR 1900 series vide mid-term review investigation and the same was retained in the first sunset review investigation. The scope of product under consideration in the present second sunset review investigation remains the same, viz.

all grades of Styrene Butadiene Rubber (SBR) 1900 series, which refers to High Styrene Resin Masterbatch or Emulsion Resin Rubber Masterbatch.

(ii) SBR 1900 series is a blend of masterbatch of two latexes- Styrene Butadiene Rubber Latex and High Styrene Resin Latex. SBR 1900 series are synthetic rubbers since they meet the technical definition of rubber.

(iii) It is classified under subheading no 40.02 at four digit level. It has been categorized as rubber under subheading 4002.19 (Styrene Butadiene Rubber with Styrene content of over 50%). In fact, when the styrene content of the grade is increased further, the grades can be cleared under subheading 3903.90 of the Customs Tariff Act. However, the classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present sunset review investigation.

(iv) The grades of SBR 1900 series are normally described in terms of Styrene content and Mooney viscosity in the product. The percentage content of the Styrene and Mooney viscosity in SBR 1900 series differentiate one grade of SBR 1900 series with the other grades. All the grades are interchangeably used by fine-tuning the recipe at the application stage. Indian industry produces the grades of SBR 1900 series which are equivalent of all those grades being produced by the exporters/producers in the subject countries.

(v) Exporter from Korea RP has misled the Designated Authority by claiming that KHS-68 grade produced and supplied by them was not within the scope of the product under consideration, even when the Designated Authority has confirmed that the High Styrene resin masterbatch was within the purview of the anti dumping Duty.

(vi) KHS-58 grade is very similar to KHS-68 with the exception that the styrene content is lower in KHS-58 grade and therefore, KHS-68 is falling under chapter 40 of the Customs Tariff Act.

(vii) Flowchart of manufacturing process shows that it is a masterbatch of two latexes as is SBR 1900 series. Another internationally recognized literature by M/s. C. M. Blow also shows that SBR 1900 series refers to a Masterbatch. KHS-68 is nothing but a masterbatch.

(viii) International Institute of Synthetic Rubber Producers (IISRP) has defined various SBR series. IISRP has defined SBR 1900 series as an Emulsion Resin Rubber Masterbatch. KHS-68 is also an Emulsion Resin Rubber Masterbatch.

(ix) Designated Authority in its Preliminary Findings relating to original investigation (Jan. '99) stated that SBR 1900 series (High Styrene Resin Masterbatch) is covered under PUC. KHS-68 is nothing but SBR 1900 series and is thus liable to duty.

(x) Designated Authority in its Final Findings relating to original investigations (Aug. '99) stated that as long as imported product is SBR of specified series ADD should be attracted (regardless of the Customs Heading under which it is imported). Accordingly, the Customs Department has to assess whether the item imported is SBR of specified series and levy ADD.

(xi) The order of the Designated Authority in the original investigation was challenged by some interested parties before CESTAT. CESTAT in its Order stated, *inter-alia*, that ADD is on SBR whether imported under 4002.19 or 3903.90. Accordingly, the ADD is imposed on both Customs Codes.

(xii) Customs Dept. has levied ADD on imports of KHS-68. One of such levy was challenged by Relaxo before CESTAT and misrepresented that the product involved was not an SBR. CESTAT held that the Anti Dumping Duty was wrongly collected. However, the Ministry of Finance has challenged the order of CESTAT before Supreme Court. Customs Dept. has thereafter instructed all customs houses to collect

Anti Dumping Duty on imports of KHS-68 reported in the Country. Subsequent consignment of KHS 68 made by Relaxo was again levied Anti Dumping Duty.

(xiii) Relaxo again challenged the order and eventually filed appeal before CESTAT. However, by this time, since the Ministry of Finance had come to know about misrepresentations before CESTAT, the Ministry of Finance brought in sufficient evidence before CESTAT, including Technical information about the product, which was suppressed by Relaxo and the exporter from Korea. CESTAT, after detailed arguments by all parties, including detailed cross examinations, held that the representations by Relaxo were incorrect and the Customs Dept. should check the matter afresh. Accordingly, the matter was remanded back to Customs Dept. Customs Dept. after reconsideration of all the facts & circumstances relating to KHS-68, has confirmed that Anti Dumping Duty was required to be levied on KHS-68.

(xiv) KKPC, the company producing and selling KHS-68, had been advertising KHS 68 as SBR for many years from the early 90's. Only when the issue of antidumping duty arose, in order to circumvent the antidumping duty and in order to suppress vital facts, the advertisement has been changed to show that KHS 68 is High Styrene Resin. The essential properties, functions & uses and customers remain the same for the product inspite of change in details.

(xv) KKPC's Brochures clearly show KHS 68 as a High Styrene Rubber. It is to be noted that the Company shows this product as a "Rubber" and not a "resin" or "plastic", as the company is now attempting to claim.

(xvi) IIT Kharagpur – Polymer Dept. has given an opinion that KHS 68 should fall under SBR 1900 series. Similar opinions have been given by a number of other independent organizations and experts.

(xvii) The levy of Anti Dumping Duty on KHS-68 was challenged before the Hon'ble High Court at Calcutta. The Hon'ble High Court (in Dec. '01) after hearing the entire matter held that KHS-68 was liable to Anti Dumping Duty.

(xviii) The end use of the KHS 68 is identical to the SBR 1900 series produced by the domestic industry and other producers world over, i.e., footwear application. Numerous letters of consumers are on record stating that KHS 68 is interchangeably being used with the domestic producers' SBR 1900 series and/or SBR 1900 series rubber being supplied by other producers world over.

(xix) In the Mid-term Review investigations conducted by the Designated Authority, it has been re-iterated that product under consideration SBR 1900 series is High Styrene Resin Masterbatch. KHS 58, KHS 65 & KHS 68 are included under the head of High Styrene Rubber. The applications are common for these grades.

(xx) The KKPC's literature shows KHS 68 as a HSR / High Styrene Resin Masterbatch; the manufacturing process is explained as a blend of SBR Latex and High Styrene Resin Latex, which meets the exact definition of SBR 1900 series.

(xxi) Domestic industry referred to the website of M/s. KKPC wherein it was found that the company has shown various products under the head of "synthetic rubber" and "synthetic resins". It is found that High Styrene Rubber is included under the head of synthetic rubbers. Further the web-page / literature on High Styrene Rubber (HSR) elaborates the product as High Styrene Resin Masterbatch.

(xxii) Since SBR 1900 series covers High Styrene Resin Masterbatches, it follows that all the grades, which are High Styrene Resin Masterbatches, are covered under SBR 1900 series. Accordingly, KHS 68 is very much within the scope of product under consideration.

(xxiii) It is argued by the exporters that in the light of Supreme Court decision, Designated Authority cannot review the issue that whether the KHS-68 is SBR 1900 series or not.

However, the Supreme Court has not given a decision on merit. It has only attempted to interpret the decision of designated Authority. In that case, it cannot be said that the Designated Authority cannot review this issue.

- (xxiv) The sole imports during the earlier SSR were of KHS 68 and Designated Authority determined dumping, injury and causal link recommending an extension of duty. Therefore, it cannot be said that Designated Authority has considered in the past that KHS 68 is not an SBR 1900 series.
- (xxv) Technical specifications of SBR 1900 series produced by the domestic industry are similar to those being exported from the subject countries. Also, it is technically and commercially substitutable with SBR 1900 series imported from the subject countries. Imported and domestically produced material is used interchangeably with direct competition between the two products. Both are alike in all essential, physical and technical characteristics.
- (xxvi) The issue of like article has been settled by the Designated Authority in earlier investigations as well as CEGAT wherein the subject goods produced by the domestic industry and the subject countries were considered as like articles.

D.2. Views of the importers, consumers, exporters and other interested parties

- 9. The following submissions have been made by the importers (M/s Paragon Rubber Industries and M/s paragon Polymer Products Pvt. Ltd.):
 - (i) The submissions made in Oral hearing for the inclusion of KHS-68 never formed the part of the application and were raised for the first time.
 - (ii) Scope of the product cannot be enhanced at this stage of review.
- 9.1 The following submissions have been made by M/s Korea Kumho Petrochemical Co. Ltd, Seoul, Korea (KKPC)
 - (i) All types of SBR were not included in the investigation and it is against the order of the Supreme Court to classify SBR under Customs heading 3903.90.
 - (ii) The designated Authority in its preliminary finding has held that SBR under 3903.90 is not product under consideration. Also in its Final finding it was held that KHS 68 falling under Chapter 39 is beyond the purview of investigation.
 - (iii) Including SBR under Customs heading 3903.90 will be contempt of the Supreme Court.
 - (iv) Following the order of the CEGAT, the Designated Authority has broadened the scope of product under consideration in MTR and SSR.
 - (v) The scope of the product under consideration cannot be modified in a Sunset review investigation. In fact, the present is the second Sunset review.

D.3. Examination by the Authority

- 10. The Authority notes that M/s Apcotex Industries Ltd has argued that KHS-68 is a SBR and falls within the scope of the PUC and that the exporters and importers have misled the Authority to hold that "Elastomer Resin KHS 68" is not under the nomenclature of "Synthetic Rubber" and that significant imports of KHS 68 have been made during the POI.

11. It is, however, noted that in the final findings dated 2nd June 1999, in its para 7, the Authority has recorded as follows:

"7... the Authority observes that the item cleared under chapter 39 is "Elastomer Resin KHS 68" and thus it is not under the nomenclature of "Synthetic Rubber". In view of this, the Authority does not find justification to cover item falling under sub-heading 3903.90 for the purpose of imposing antidumping duty. However, the Authority agrees with the argument of the petitioner to the extent that product under consideration is Synthetic Butadiene Rubber of specified series as stated, irrespective of custom heading. The Authority thus holds that whereas it is not justified to cover all items falling under the sub heading 3903.90, for the purpose of imposing anti-dumping duty in present case the anti-dumping duty however is payable on Styrene Butadiene Rubber of specified series as stated, even if it is sought to be cleared under any other heading of the Custom Tariff Act. The Custom Authorities are at liberty and expected to classify the goods correctly, if the goods offered for clearance are not classified correctly."

12. It is observed that the product under investigation in the original investigation was all grades of Styrene Butadiene Rubber (SBR) classified under customs heading nos. 3903.90 and 4002.19 of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from Japan, Korea RP and USA. The original investigation concluded vide notification dated 2/6/99 recommended duty on SBR 1500, 1700 & 1900 series. However, the scope of duty was restricted to SBR 1900 series vide mid-term review notification dated 3rd July 2001 and was retained so in the first sunset review investigation. Thus, the product under investigation in this sunset review investigation remains the same, viz. all grades of Styrene Butadiene Rubber (SBR) 1900 series and does not include "Elastomer Resin KHS 68".

13. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present Sunset review investigation.

E.1. Scope of the Domestic Industry

Submissions made by the Domestic industry

14. M/s. Apcotex Industries Ltd., has made the following submissions:

In the original investigations, petition was filed by M/s. Synthetics & Chemicals Limited. Subsequently, the company was forced to suspend its production. At the time of review, M/s. Apar Industries Limited and Apcotex Industries Limited constituted domestic industry. In the present period, there are only two producers of SBR in India. Apcotex is a major producer of the subject goods in India.

E.2. Submissions made by the importers, consumers, exporters and other interested parties

15. The following submissions have been made by the importers (M/s Paragon Rubber Industries and M/s paragon Polymer Products Pvt. Ltd):

- (i) Present response is without the Authorization on behalf of Domestic Industry. The declaration that the domestic industry has not imported the subject goods or is not related to exporter or importer is without certification. No examination has been conducted by the Authority in this regard.
- (ii) According to the Trade Notice No. 3/2007, Designated Authority is at liberty to close the investigation if duly substantiated application is not filed by the Domestic industry.
- (iii) Apcotex has unnecessarily treated all the information regarding injury and causal link as confidential without giving proper reasons. There is no proper indexation done with respect to the non-confidential information. Such information is therefore to be rejected.

16. No other interested party has made any submission in this regard.

E.3. Examination by the Authority

17. At the time of the initiation of this review investigation, Rule 2(b) of the AD Rules read as follows:-

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only":

18. However, the Rule 2(b) of the AD Rules has recently been amended to read as:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only"

19. In the present review investigation, the Authority notes that the M/s Apcotex Industries Limited is a major producer of the subject goods in India. Therefore, M/s Apcotex Industries Limited constitutes 'domestic industry' within the meaning of the AD Rules.

F.1. Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping

20. Submissions made by the Domestic Industry

- None of the exporters and producers from the subject countries has responded to the Designated Authority by filing the exporter's questionnaires responses. M/s Korea

Kumho Petrochemical Co. Ltd, Seoul, Korea (KKPC) has also not filed any questionnaire response, even though the company has exported the subject goods in the investigation period. Such being the situation, the exporters/producers from all the subject countries should be treated as non-cooperative.

- Domestic industry has provided a detailed estimation of normal value in the subject countries, which may be adopted for determination of dumping margin in the present review.
- The imports shown by DGCI&S cannot be considered. SBR 1900 series is classified under customs sub-heading no. 4002.1902 and 3903.9000. The importers are getting it cleared under other sub-headings. The official statistics of the Government of India published by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistic, does not, therefore, exhibit true and complete picture with regard to volume and value of the imports. They have provided evidence establishing that the importers are getting SBR 1900 series cleared under other sub-headings also. Furthermore, the imports under customs sub-heading 3903.9000 cover other products besides SBR series. It is therefore submitted that the imports shown by DGCI&S cannot be considered.
- They have compiled import statistics as per information made available by the Customs and compiled by secondary sources. Such imports of SBR 1900 series are being compiled by Polymers Plastics & Rubber Journal (PPR), based on the information made available in the Customs Daily Lists. It is submitted that the imports compiled as per information published by PPR at the best can be considered as minimum imports of the subject goods in India. The domestic industry has thus determined the export price for the reasons stated above, as per the imports reflected in PPR.
- It may also be noted that although the imports have been cleared under Chapter 40 of the Customs Tariff, the manufacturers from these countries are in a position to produce various grades, some of which would fall under chapter 39 of the Customs Code. Hence, it is imperative that the Anti-dumping duty is imposed on all the relevant Customs Codes.
- Considering the normal value and export price it would be seen that exporters from the subject countries have continued to export at dumped prices in the Indian market. None of the foreign exporters or producers has provided information in the prescribed form and manner. Also it is not established by any of the foreign exporters or producers that there is “no dumping” or “no likelihood of dumping”. Exporters have failed to establish that the dumping is unlikely in the event of revocation of anti-dumping duty.
- In a Sunset review, the Authority is required to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to arrive at a decision to continue or vary or remove the duty so as to offset dumping. It has, *inter alia*, submitted the following:
 - (i) That the domestic industry has suffered injury from the dumped imports for quite some time as confirmed by the original determination and subsequent review determinations. There is a great possibility that the expiry of duty will result in

flooding of the material in the Indian market. That the domestic industry did not suffer significant injury in the current period due to low volume of the imports. However, expiry of the anti dumping duties is likely to result in increased volumes at dumped prices from the subject countries causing injury to the domestic industry.

- (ii) That, even after exporting the subject material and selling in their domestic market, the producers in these countries are having excess unutilized capacities. Evidently surplus capacities have been created considering the export markets. Expiry of the present duty would therefore result in significant exports to the Indian market.
- (iii) That the imports reported in the investigation period were undercutting the domestic prices. Therefore, in the event of revocation of anti dumping duties, the domestic industry is likely to face decline in demand for its product. This would have significant depressing/suppressing effect on the domestic industry.
- (iv) The burden of proof is on the exporter that the dumping is unlikely to continue or recur in the event of revocation of the anti dumping duties.

F.2. Submissions made by the Exporters/Importers/Other interested parties

21. Neither any exporter or producer has filed the questionnaire response in the form and manner prescribed, nor has any interested party offered any comment or submissions with regard to the Normal value, Export price and determination of the dumping margin.

F.3. Examination by the Authority

22. It is seen that the subject goods have only been imported from Japan to the extent of 29 MTs and there has not been any imports of the subject goods during the POI from Korea RP and USA. It is further noted that out of the total demand of about 9000 MTs, the imports from the subject countries account for only 29 MTs. Thus, the Authority observes that imports of this quantity of the subject goods may not have had a significant adverse impact on the performance of the domestic producers. It is, however, possible that the imports may not have been made due to the imposition of the anti dumping duty in force.

23. Therefore, as mandated under the law, the Authority further examined the likelihood of recurrence of dumping, in case the anti dumping duty in force is allowed to cease. It is noted that a specific questionnaire, *inter alia*, eliciting information regarding likelihood of recurrence of dumping and consequent injury was sent to all known exporters/producers from the subject countries. However, no exporter/producer has responded to the same and thus has not co-operated in this investigation. Thus, the Authority has no recourse but to rely on the facts available on record to examine the likelihood of recurrence of dumping. Therefore, the Authority has examined the issue of likelihood of recurrence of dumping and consequent injury on the basis of best information available.

24. The Authority tried to find the relevant data which could establish the prices at which the subject goods have been exported from the subject countries to the third country markets. For this purpose, the data as made available by Korea International Trade Association (KITA), UNCOMTRADE and World Trade Atlas were checked and it was found that the data was not available for the subject goods and instead covered all types of SBR. It was found that the Customs classification is not dedicated for the product and the classification includes other types of SBR as well.

25. The domestic producer has submitted a report, namely World Rubber Statistics, 2008, of IISRP (a leading international journal relating to this product, which provides details of capacities available with various global players and country wide consumption patterns). From a perusal of the report, it is noted that globally the producers report the capacities for SBR as a whole, irrespective of their types. However, a perusal of the journal shows that there are surplus capacities to manufacture SBR in the subject countries, which also includes the subject goods. Besides, the domestic industry has contended that some of the global producers, in fact, interchangeably use the production facilities for producing different kinds of SBR. Even the web-sites of some of the producers of the subject goods were seen but the relevant information about the capacities and other details thereof was not found. While these websites did not disclose the information with regard to production, capacity, demand etc. dedicated for the subject goods but only revealed the information in respect of various products produced by them.

26. The Authority, however, notes that 29 MT of the subject goods have been imported from the subject countries during the POI. In view of the non-cooperation from the exporters/producers from the subject countries and in absence of the availability of relevant data in respect of the subject goods; the Authority considers that in case the anti dumping duty ceases to operate, the imports of the subject goods from the subject countries are likely to enter into India at similar prices. Besides, from the data available in respect of the capacities of SBR and consumption patterns thereof in the subject countries in the afore-stated journal, it is quite possible that these idle/surplus capacities could be utilized for exporting the subject goods to India in the event the anti-dumping duty in force ceases to operate. Thus, in a situation when there are unutilized capacities, even if it is assumed that third country exports would not be diverted to Indian market (in the absence of the relevant data in respect of exports of the subject goods from the subject countries to the third country markets), the likelihood of recurrence of dumping in the event of cessation of the anti-dumping duty is apparent. Accordingly, the likelihood of dumping and the dumping margin has been estimated on the basis of the best information available on record. The dumping margins so estimated works out to 323.55 US\$/MT in respect of Japan; 393.38 US\$/MT in respect of Korea RP and 493.71 US\$/MT in respect of USA.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

27. The Authority notes that this being a Sunset review of the anti-dumping duty already in force, likelihood of continuation or recurrence of material injury needs to be examined in the context of actual or likely imports of the subject goods from the subject countries.

G.1 Likelihood of Continuation or Recurrence of Injury**Submissions made by the Domestic Industry**

28. The submissions made by the domestic industry with regard to injury and causal link, in brief, are as follows:

- (i) WTO Rules states that the anti-dumping duties should remain in force till such time that the product continues to be exported at dumped prices and the domestic industry continues to be injured or there is a possibility of recurrence of dumping in case duties are revoked with consequent possibility of recurrence of injury to the domestic industry. Therefore, duties should remain in force to the extent necessary to counteract the dumping which is causing injury.
- (ii) Indian Rules also states that the anti-dumping duty once imposed shall remain in force unless designated Authority in a Review is of the opinion that the cessation of such duty is unlikely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
- (iii) In accordance with Rule 11, in the sunset review investigation, injury to the domestic industry has to be examined on a *mutatis mutandis* basis.
- (iv) The exporters from Japan and Korea continued dumping of the material in the Indian market. Though the volume of imports is low, the same was clearly at the dumped prices.
- (v) The landed price of imports which is below the domestic selling price has further decreased. Revocation of anti dumping duty will therefore result in price undercutting.
- (vi) The margins of dumping from the subject countries are more than the limits prescribed. Though the export prices have increased subsequent to previous investigation conducted by the Designated Authority, the export prices have increased in Rupee terms only and not in US \$ terms. Actual realization to the exporter (which is linked to US \$) has declined. Moreover, the cost of production of the Foreign Producers has increased due to increase in the raw material costs.
- (vii) The position of the domestic industry improved significantly in the period as the dumped imports were not available in the market. Further, it would be seen from the submissions given below that should the Anti-dumping duty be revoked, the injury to the domestic industry would recur.
- (viii) Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the like goods offered by the domestic industry in the Indian market. The Authority is, therefore, requested to assess injury to the domestic industry cumulatively from the subject countries.
- (ix) Sufficient freely disposable capacities exist in the exporting countries. The consumption in the exporting countries is far less than their capacities built-up and the exporters in these countries have no option but to look for some markets to sell their surplus. Such being the situation, revocation of Anti-dumping duty at this stage would result in flooding of the imports in the Country. It would not be difficult for these Foreign Producers to export volumes to the extent of Indian demand.

G.2. Submissions of other interested parties

29. The following submissions have been filed by M/s Paragon Rubber Industries and M/s Paragon Polymer products Pvt. Ltd (Importers). No other interested party has advanced any argument on injury & causal link. M/s Paragon Rubber Industries and M/s Paragon Polymer products Pvt. Ltd have, *inter alia*, contended that:

- (i) Apcotex has unnecessarily treated all the information regarding injury and causal link as confidential without giving proper reasons. Also no proper indexation has been done with respect to the non-confidential information. Such information is therefore to be rejected.
- (ii) During the hearing, no submissions were made by Apcotex on their case on dumping, injury and causal link.
- (iii) No injury is claimed by Apcotex in its application and by its own admission that the global meltdown is the cause of the deterioration if any. Therefore, it is the Authority's obligation to examine the likelihood of dumping and injury.
- (iv) Continuation of duties cannot be claimed from USA as there are no imports from the country and hence no causal link has been established.
- (v) No evidence of divergence of exports from third countries to India, pricing behaviour or their capacities, demand, sales projections or likely prices in other markets has been provided.
- (vi) Designated Authority has not provided access to the public documents. There is no proper maintenance of the public file.
- (vii) There is a flaw in the calculation of the landed value as the data for excluded products is also included.
- (viii) Designated Authority should make available the data relied to file questionnaire response by Apcotex, non-confidential version of the correspondences between the Apcotex and other parties, the T/T DGCI&S data and data procured from other sources, DGCI&S data for Styrene Monomer and Butadiene, the methodology for the calculation of the normal value, the basis for taking U.S.A power rates, the evidence of adjustments to calculate the export price and the source of the sales of other Indian producers, the evidence of the capacities of producers from the subject countries.
- (ix) The CIF price is miscalculated.
- (x) There is duplication of the entries for 2005-06.

G.3. Examination by the Authority

30. The Authority has taken note of the arguments on injury examination and addressed the issues raised at appropriate places. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and the arguments of the interested parties.

31. It is stated that the public file has been duly maintained and has been made accessible to all the interested parties from time to time as per mutual convenience.

32. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the

dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

33. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry Para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows.

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments."

G.3.1. Likelihood of Continuation of Injury

34. The Authority has first examined whether there is likelihood of continuation of injury to the domestic industry on the basis its performance during the period of investigation (POI).

35. For the purpose of current injury analysis the Authority has examined the volume and prices effects of imports of the subject goods from subject countries on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal link between dumping and injury, if any.

Volume effect

a) Assessment of Demand

36. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of the domestic industry and other Indian producer have been added to the total imports into India, which has been summarized as under:

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Imports from Subject countries					
Japan	MT	86	248	26	29
Korea RP		-	-	-	-
USA		-	-	-	-

Imports from other countries	MT	50	7	-	33
Total imports	MT	136	255	26	61
Sale of domestic industry	MT	4473	3742	6794	4531
Sales of other Indian Industry	MT	4752	4090	7116	4463
Total Demand	MT	9,361	8,087	13,936	9,055

The Authority notes that there is significant demand of the product under consideration in the period of investigation though the demand of the product has declined in the POI as compared to the base year and as well as the immediately preceding year. There has also been a decline in the volume of imports from the subject countries over the years and only a marginal increase in the period of investigation as compared to the immediately preceding year.

b) Import volumes and market share

37. Annexure-II (ii) of the AD Rules provides that “while examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports either in absolute term or relative to production or consumption in India ...”. Thus, with regard to the volume of the dumped imports, it has been examined whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

38. The table below summarises the position with regard to import volumes and market share: -

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Imports from Subject countries					
Japan	MT	86	248	26	29
Korea RP	MT	-	-	-	-
USA		-	-	-	-
Imports from other countries	MT	50	7	-	32
Total Imports	MT	136	255	26	61
Indian Production	MT	9157	7882	14083	9189
Demand	MT	9,361	8,087	13,936	9,055
Subject imports in relation to					
Total Imports	%	63.58	97.12	100.00	46.91
Production	%	1.96	6.54	0.38	0.61

Consumption	%	0.92	3.07	0.19	0.32
Market share of domestic industry in demand	%	47.48	46.27	48.75	50.04

From the above, the Authority notes that:

- (i) The demand of the subject goods has been in the range of 9,361 to 9,055 except during the 2007-08 period. The domestic industry has claimed that the demand had increased in 2007-08 due to increase in the prices of natural rubber which led to the substitution of natural rubber with the product under consideration.
- (ii) With the negligible volume of dumped imports from the subject countries in the period of investigation, the market share of the subject countries has also declined in comparison with the base year. There are no imports from USA and Korea RP; whereas the imports from Japan are not in significant volumes.

G.3.2 Price effect of the dumped imports on the Domestic Industry

39. In order to ascertain the price effect of the imports of the subject goods from subject countries on the domestic industry, the Authority has examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
40. In order to assess the extent of price undercutting, the Authority has compared the net sales realization of the domestic industry with the landed value of the imports. The net sales realization was arrived, after deducting all rebates and taxes. The landed value of the imports was compared with the net sales realization of the domestic industry, even after considering the anti-dumping duties in force and it is noted that the Landed value of the subject goods from the subject countries including the applicable customs duty is significantly lower than the net sales realization of the domestic industry.

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Net Sales Realization	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	107	134
Landed Value	Rs./MT	***	***	***	***
Trend		100	106	111	102
Antidumping duty Benchmark	Rs./MT	***	***	***	***
Trend		100	103	92	103

Price undercutting amount	Rs./MT	(***)	(***)	(***)	***
Trend		(100)	(100)	(128)	36
Price undercutting %	%	(***)	(***)	(***)	***
Trend		(100)	(93)	(120)	27

Price suppression/depression

41. In order to assess whether the imports from the subject countries were suppressing/depressing the prices of the domestic industry, the Authority has compared the cost of production and net selling price of the domestic industry along with the landed price of imports over the injury period, which is given in the following table:

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Cost of Production	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	97	113
Net Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	105	134
Profit/Loss	Rs./MT	(***)	(***)	(***)	***
Trend	Indexed	(100)	(178)	(31)	39

The Authority notes that both the cost of production and the net selling price increased in 2006-07 and then dipped in 2007-08 and again increased in the POI. The domestic industry has claimed that the increase was a result of global increase in the input costs. Apparently, the domestic industry was able to increase its prices appropriately along with the increase in the cost of production. However, this needs to be seen in the context that there have not been any significant volume of imports of the subject goods from the subject countries during the POI. Therefore, it further needs to be examined, whether the situation is likely to be the same, once the anti-dumping duties cease to operate.

Economic Parameters relating to the Domestic Industry

42. Annexure II to the AD Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to determination of consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude

of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

Production, sales, capacity and capacity utilization

43. The production, sales, capacity & capacity utilization of the domestic industry has been as follows:

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	(POI)
Capacity	MT	10,000	10,000	10,000	10,000
Production	MT	4,405	3,792	6,967	4,726
Capacity utilization	%	44.05	37.92	69.67	47.26
Domestic sales	MT	4,449	3,742	6,794	4,531
Demand	MT	9,361	8,087	13,936	9,055
Production in % of demand	%	47.06	46.89	49.99	52.19
Sales in % of demand	%	47.53	46.27	48.75	50.04

It is noted that the performance of the domestic industry in terms of production, capacity utilization and sales has moved in tandem with the demand. However, the domestic industry has claimed that performance of the domestic industry would again be adverse if the anti-dumping duties in force cease to operate, as (a) there is excess capacity in subject countries; (b) there is a huge domestic market in India and (c) the price attractiveness of Indian market as would be evident from the existence of significant price undercutting during the POI.

Profitability

44. The cost of production, net sales realization & profit/loss of the domestic industry is shown below:

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Cost of Production	Rs./MT	***	***	***	***
Trend		100	116	97	113
Net Sales Realization	Rs./MT	***	***	***	***
Trend		100	108	105	134
Profit/Loss	Rs./MT	(***)	(***)	(***)	***
Trend	Rs./MT	(100)	(178)	(31)	39

The Authority notes that the domestic industry has improved its performance and has started earning profits in the POI.

Market share

Market Share in Demand	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Subject Countries					
Japan	%	0.92	3.07	0.19	0.32
Korea RP		-	-	-	-
U.S.A		-	-	-	-
Other Countries	%	0.53	0.09	-	0.36
Domestic industry	%	47.78	46.27	48.75	50.03
Other domestic producer	%	50.77	50.57	51.06	49.29

A comparison of the sales of the domestic producers and imports from the subject countries shows that there is low volume of imports, which may be due to the existence of the anti-dumping duties. However, if the present duties cease to operate, it needs to be further examined, whether the domestic industry is likely to suffer loss on profitability or the market share due to the likely presence of the dumped imports, if any, in light of the significant price difference.

Employment and Wages

45 The position with regard to employment, wages and productivity is as follows:

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Employees	No.	***	***	***	***
Trend		100	99	111	104
Wages	Rs.lacs	***	***	***	***
Trend		100	106	132	158
Productivity per day	MT/day	12.24	10.53	19.35	13.13

The Authority notes that the productivity of the domestic industry has apparently not suffered.

46. Return on investments and cash flow

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)

ROI - GFA Basis	%	(***)	(***)	(***)	***
Trend	Index	(100)	(142)	(37)	46
ROI - NFA Basis	%	(***)	(***)	(***)	***
Trend	Index	(100)	(144)	(36)	58
Cash Profit	Rs.Lac	(***)	(***)	(***)	***
Trend	Index	(100)	(201)	(32)	140

The Authority notes that with the decline in the import volumes, the return on investment has improved. In absence of any significant volume of the imports entering the Indian market during the period of investigation, the domestic industry's performance has taken a positive turn in respect of ROI and cash profit. However, with the current price difference between the landed value of the subject goods and the net sales realisation and as well as the non-injurious price of the domestic industry; it needs to be further examined, whether there is likelihood of injury to the domestic industry, if the anti-dumping duties in force cease to operate.

47. Inventories

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Average Inventories	MT	212	127	92	109

It is seen that the inventories of the domestic industry have increased during the period of investigation as compared to the previous year, which appears to be due to the decline in demand in the POI as compared to the previous year. However, the inventories have declined in comparison to the base year.

It has been claimed by the domestic industry that the withdrawal of anti-dumping duty is likely to lead to recurrence of dumping, which would cause injury to the domestic industry and that would include increase in the inventory levels as well.

48. Ability to raise capital

The Authority notes that the domestic industry does not have too many operations and any adverse performance of the product is likely to impact its ability to raise capital.

Magnitude of Margin of Dumping

49. The Authority notes that though significant volumes of imports of the subject goods have not been made during the period of investigation, but the volume of imports that have been made during the POI, being in commercial quantities, the dumping margin is quite significant. The dumping margin in the period of investigation is also indicative of likely future behaviour of the exporters from these countries.

Growth

50. The Authority notes that though there has been a positive growth in terms of most of the parameters; but it needs to be further examined, whether the domestic industry would continue to perform in a similar manner, once the anti-dumping duties in force cease to operate.

Magnitude of Injury and Injury margin

51. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared to the landed value of the exports from the subject countries for determination of the injury margin during the POI. Thus compared, the injury margin works out as under:

NIP	Rs./MT	***
Landed Price	Rs./MT	***
Injury Margin	Rs./MT	***
Injury Margin (%)	%	***
Range	%	10-15

Likelihood of recurrence of injury

52. Submissions made by the domestic industry

The domestic industry has contended that:

- the exporters/producers in the subject countries are likely to resort to dumping of the subject goods in the Indian market due to the excess capacities in the subject countries.
- None of the interested parties has participated and co-operated in the present investigation and thereby have failed to establish that there is no likelihood of the continuation or recurrence of dumping and consequent injury in the event of revocation of the anti dumping in force.
- the price difference between the domestic and imported material has been significant and that there is no reason to believe that the subject countries would not divert significant volumes of the subject goods to the Indian market in case the anti dumping duties are withdrawn, more so when freely disposable capacities exist with the foreign producers.
- It has not been demonstrated by the exporters that withdrawal of anti-dumping duty would not lead to likelihood of recurrence of dumping and injury to the domestic industry and continued imposition of the duty was unnecessary to offset dumping.

Examination by the Authority

53. As stated above, while apparently the domestic industry has not suffered injury during the POI, due to small volume of imports of the subject goods from the subject countries; therefore it has been further examined whether there is likelihood of recurrence of dumping and consequent injury, if the anti-dumping duties cease to operate.
54. The arguments and submissions made by the interested parties have been examined; and all such factors that have been brought to the notice of the Authority have been evaluated to find out whether there is a likelihood of recurrence of injury in the event of cessation of the anti-dumping duty. For this purpose, parameters such as capacity, production, landed value of imports, surplus capacities in the subject countries, likelihood of exports, domestic demand, net sales realisation of the domestic industry, the non-injurious price as determined by the Authority etc. have been considered.
55. The Authority has noted that the subject goods have been imported in the Indian market (although in small quantity) at dumped prices, despite the existence of the duties in force. It is likely that the subject goods from the subject countries may be exported at similar prices from the subject countries in the event of cessation of the anti-dumping duty, as has already been noted in the relevant section of these findings.
56. Therefore, the Authority has further examined the likelihood of injury, in case of recurrence of dumping, if the anti dumping duties in force cease to operate. It has been noted that imports of small volumes (but in commercial quantities) have been effected during the POI at dumped prices. No exporter/producer has co-operated in this investigation by submitting the questionnaires' response. Whereas the domestic industry has provided information regarding capacity, production and demand of the subject goods of the exporting countries based on a report, namely World Rubber Statistics, 2008, of IISRP (a leading international journal relating to this product, which provides details of capacities available with various global players and country-wide consumption patterns). From the perusal of the report, it is noted that there are surplus capacities to manufacture SBR in the subject countries, which also includes the subject goods. Besides, the domestic industry has contended that some of the global producers, in fact, interchangeably use the production facilities for producing different kinds of SBR.
57. In view of the non-cooperation, the Authority has little recourse but to determine the likelihood of injury on the basis of the facts available on record. It has been seen that the landed value of the imports during the POI have been significantly lower than the net sales realization and the non-injurious price of the domestic industry. Assuming that the price trends remain similar, it is likely that the domestic industry's performance would be adversely impacted due to the recurrence of dumping of the subject goods.
58. Besides, it is observed that the subject countries are exporting to a number of countries and therefore possibilities of diverting third country exports to India are not ruled out.

TABLE

Country	Capacity	Demand	2008 ('000 MT)				
			Surplus Capacities	Exports	Imports	Derived Production	Available surplus capacities
Japan	564	416	148	148	98	466	246
USA	1,125	767	358	313	278	802	636
Korea RP	516	229	287	453	31	651	318
India*	17	9	8	0	0	9	8

Source: IISRP- World Rubber Statistics, 2008, Export-import data from UNCOMTRADE.

- Indian data is for Product under Consideration only and other country data is for SBR as a whole.

59. Considering that there is significant demand of the subject goods in the country and that the subject countries have the potential to raise their production and export volumes, the cessation of the anti-dumping duties is likely to make the Indian market attractive to the exporters/producers from the subject countries, by reason of price. In such an event it is likely that the imports of the subject goods are effected at similar prices at which they have been made during the POI (albeit in small volumes). Assuming so, there is likely to be a case of significant price undercutting and as well as of significant price underselling that is likely to adversely impact the domestic industry.

60. Further, the possibility of lowering the prices by the exporters/producers from these countries cannot be ruled out in view of dumping and likelihood of recurrence of dumping. Such price behaviour of exporters/producers from the subject countries coupled with their ability to deliver significant quantities of the subject goods is likely to have a price depressing impact on the price-sensitive domestic market. Thus, the Authority notes that in the event of cessation of the present anti-dumping duties, there is likelihood of recurrence of injury to the domestic industry.

H. Causal Link

61. The Authority has examined the submissions with regard to the significance and relevance of causal link in a sunset review investigation. It is important to note that under Section 9A(5) of the Act, the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties irrespective of whether there have been any imports of the product under consideration during the review investigation period or not. It was, however, examined whether other parameters listed under the AD Rules could have contributed to injury to the domestic industry. It is noted as follows:

Volume and Prices from Other Countries

62. The Authority notes that there is a significant increase in the volume of imports from the other countries. However, the injury to the domestic industry has not been caused due to these volumes as the prices of the imports from the other countries are significantly higher.

Contraction in Demand and / or Change in Pattern of Consumption

63. It is noted that the demand of the subject goods has decreased in the period of investigation as compared to the previous year. The domestic industry has, however, claimed that the demand had increased in 2007-08 due to increase in the prices of natural rubber which led to the substitution of natural rubber with the product under consideration. This fact has not been disputed by any other interested party. It has thus seen that there is no indication of any change in the consumption pattern.

Trade Restrictive Practices of and Competition between the Foreign and Domestic producers

64. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. The domestic producers compete amongst one another and at the same time compete with the landed prices of the subject goods. The price of the domestic industry is influenced substantially by the landed price of the subject goods. Moreover, no evidence has been submitted by any interested party even to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

Development of Technology

65. Neither any party has raised any issue with regard to developments in technology as being the cause of injury to the Domestic Industry, nor there appears to be any significant development in technology that the same could be the principal cause of injury to the domestic industry.

Export Performance

66. There have been marginal exports of the subject goods by the domestic industry. In any case, the Authority has considered profitability and other price parameters only in respect of domestic operations.

Productivity

67. It is noted that the productivity of the domestic industry has not suffered in the absence of dumping.

68. The Authority thus notes that other listed known factors have not caused injury to the domestic industry.

69. In determining whether dumped imports of the product are causing injury to the domestic industry, the Authority considered the following parameters:

- a) The imports are still continuing at dumped prices, though the quantum of dumped imports has remained low, which could be due to the presence of anti-dumping duty. It would be examined whether the imports of the subject goods would increase on the cessation of anti-dumping duties and whether as a direct consequence thereof, the domestic industry is likely to lose its market share.

- b) The market share of the domestic industry has remained more or less stable. It would be, however, seen whether the recurrence of dumping is likely to have any impact on the market share of the domestic industry in the event of cessation of the anti-dumping duty.
- c) Whether the imports of the subject goods are likely to undercut the prices of the domestic industry.
- d) There is an improvement in profits, return on capital employed and cash profits of the domestic industry which could be due to the presence of anti-dumping duty; therefore, it would be further seen whether the recurrence of dumping is likely to have any impact on these parameters in the event of cessation of the anti-dumping duty.
- e) Growth of the domestic industry has shown positive improvement in respect of a number of parameters, which could be due to the presence of the anti-dumping duty in force. Therefore, it would be further examined whether the recurrence of dumping is likely to have any impact on these parameters in the event of cessation of the anti-dumping duty.

I. CONCLUSIONS

70. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the likelihood of recurrence of dumping and consequent injury, the Authority concludes that:

- (i) The subject goods are likely to enter the Indian market at dumped prices if the anti-dumping duties in force cease to operate.
- (ii) The situation of domestic industry is likely to deteriorate if the existing anti-dumping duties are allowed to cease.
- (iii) The deterioration in the performance of the domestic industry is likely to be because of dumped imports from the subject countries
- (iv) Thus the anti-dumping duties are required to be extended.

J. RECOMMENDATIONS

71. Having concluded that the subject goods are likely to be exported at dumped prices, and there is likelihood of recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry, if the anti-dumping duties cease to operate. Thus, the Authority is of the opinion that the measure is required to be extended as specified in the duty table below.

72. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends continuation of the imposition of anti-dumping duties so as to remove the likelihood of injury to the domestic industry. Accordingly, the antidumping duty as per amount specified in Col 8 of the table below is recommended to be imposed in the event of acceptance of these recommendations by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Duty Table

Sl. No	Heading/ Sub- heading	Description of goods	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	4002.19	<i>Styrene Butadiene Rubber of 1900 series</i>	Korea RP	Any country other than those attracting anti- dumping duty	Any	Any	0.0689	Per kg	US\$
2	4002.19	<i>Styrene Butadiene Rubber of 1900 series</i>	Any country other than those attracting anti- dumping duty	Korea RP	Any	Any	0.0689	Per kg	US\$
3..	4002.19	<i>Styrene Butadiene Rubber of 1900 series</i>	Japan	Any country other than those attracting anti- dumping duty	Any	Any	0.1045	Per kg	US\$
4.	4002.19	<i>Styrene Butadiene Rubber of 1900 series</i>	Any country other than those attracting anti- dumping duty	Japan	Any	Any	0.1045	Per kg	US\$
5.	4002.19	<i>Styrene Butadiene Rubber of</i>	USA	Any country other	Any	Any	0.197	Per kg	US\$

		<i>1900 series</i>		than those attracting anti- dumping duty					
6.	4002.19	<i>Styrene Butadiene Rubber of 1900 series</i>	Any country other than those attracting anti- dumping duty	USA	Any	Any	0.197	Per kg	US\$

73. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of Customs except duties under Sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

74. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority